

# प्रेरणा विचार

RNI No. : UPHIN/2023/84344 ₹: 30

अप्रैल-2024 (पृष्ठ-36) गौतमबुद्धनगर से प्रकाशित



जन-गण  
का  
उत्सव



# मेरा वोट मेरा कर्तव्य हम वोट जरूर डालेंगे

लोकतंत्र के महापर्व में मताधिकार का प्रयोग कर देश के भाग्य विधाता बनें। आपके एक वोट से भारत की एकता, अखंडता एवं संस्कृति और मजबूत होगी।

स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान।  
वोटिंग कर दिखाएं निशान।।  
-प्रेरणा विचार पत्रिका



## प्रेरणा विचार

वर्ष -2, अंक - 4

RNI No. UPHIN/2023/84344

### संरक्षक

मधुसूदन दादू

### सलाहकार मंडल

श्री श्याम किशोर, डॉ. अनिल निगम  
प्रो. (डॉ.) हरेन्द्र सिंह

### संपादक

डॉ. मनमोहन सिंह शिशौदिया

### कार्यकारी संपादक

डॉ. प्रियंका सिंह

### प्रबन्ध संपादक

मोनिका चौहान

### समन्वयक संपादक

राम जी तिवारी

अध्यक्ष प्रीति दादू की ओर से  
मुद्रक/प्रकाशक डॉ. अनिल त्यागी द्वारा  
चंद्र प्रभु ऑफसेट प्रिंटिंग वर्क प्रा. लि.  
नोएडा से मुद्रित तथा प्रेरणा भवन  
सी-56/20 सेक्टर-62 नोएडा,  
गौतमबुद्धनगर से प्रकाशित

### संपादकीय कार्यालय

प्रेरणा शोध संस्थान ब्यास,  
सी-56/20 सेक्टर-62, नोएडा - 201309  
दूरभाष : 0120 4565851,  
ईमेल : prenavichar@gmail.com  
वेबसाइट : www.premasamvad.in

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त  
विचार लेखकों के अपने हैं। संपादक का  
उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।  
सभी विवादों का निपटारा नोएडा की  
सीमा में आने वाली सक्षम  
अदालतों/फोरम में मान्य होगा।

संपादक

## इस अंक में



भाजपा 370 पार! कांग्रेस 50 से नीचे?-5



श्रीराममन्दिर से राष्ट्रीय पुनरुत्थान की ओर-09



एक देश-एक चुनाव -13



नव ऊर्जा का पर्व नवरात्र -30

सीएए : पीड़ित मानवता के लिए वरदान.....	15
भारतीय संस्कृति को स्थापित करता एक फिल्मोत्सव.....	17
संदेशखाली का संदेश चुनाव में नहीं जाएगा खाली! .....	18
मठ-मंदिरों पर कसता सरकारी शिकंजा .....	20
घरेलू सजावट का देशी केंद्र "चौखट" .....	22
कुलांचे भर रही अर्थव्यवस्था.....	24
प्रभु श्रीराम और नदियां.....	26
नवसंवत्सर : सृष्टि का प्रस्थान बिन्दु.....	28
विशेष समाचार.....	32
क्या आप जानते हैं?.....	33
हर दिन पावन.....	34

# राष्ट्रहित पर ध्यान दें मतदाता



हर भारतीय के लिए यह आम चुनाव संकल्प को सिद्धि में बदलने के मंत्र की तरह है। जहां आपका एक वोट आने वाले समय के लिए भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान और राष्ट्र के गौरव के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। इसलिए इस बार का आम चुनाव स्व भारत के संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए एक प्रयोजन भी है। जहां से राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान, आर्थिक महाशक्ति और शक्तिशाली राष्ट्र का भाव पुनर्स्थापित होगा। इसलिए लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग कर आगामी भारत के दिशा और दशा निर्धारण में सहभागी बनें।

**लो**कतंत्र का महापर्व 19 अप्रैल से शुरू है। इसमें 96 करोड़ से अधिक मतदाता केंद्र में आने वाली सरकार की किस्मत का फैसला करेंगे। यानी यही भाग्य विधाता आगामी पांच वर्षों के देश के दिशा निर्धारक हैं। इसलिए सबसे पहले स्वयं से एक प्रश्न करना होगा कि क्या हम अपने मताधिकार के उत्तरदायित्व को लेकर सचेत हैं? क्या वोट देने से पहले राष्ट्रहित का विचार मन में है? क्या लोकतंत्र की नींव को भारतीय संस्कृति के परिदृश्य में मजबूत करने का विचार विवेक में है? यदि नहीं है, तो एक बार मन मस्तिष्क में नीर क्षीर विवेक के जरिए विचार अवश्य करिये। यह प्रश्न इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश की सभी राजनीतिक पार्टियां चाहे वो राष्ट्रीय हों या राज्यीय या प्रमुख गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल सभी के द्वारा अपनी क्षमता अनुसार लोकलुभावन वादे किये जाएंगे। मतदाता को जाति में विभाजित करने का प्रयास होगा। तात्कालिक लाभ के वो सभी वादे किये जाएंगे, जिनसे भोली भाली जनता लोभ और बहकावे में आकर मूल मुद्दों से भटक जाए। इसलिए इस दौरान एक जागरूक मतदाता को सबसे अधिक चौकन्ना रहने की जरूरत है। क्योंकि कहीं इस क्षणिक लाभ के चक्कर में दीर्घकालिक हितों की बलि न चढ़ जाये।

आज सोशल मीडिया के दौर में गांव से लेकर शहर तक सभी मतदाता जागरूक हो चुके हैं। यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग समय-समय पर तरह-तरह का प्रयास करता रहता है। ऐसे में बस जरूरत है थोड़ा सा सतर्क होकर विवेक के इस्तेमाल करने की। इस क्रम में जनप्रतिनिधि को चुनते समय केवल व्यक्तिगत लाभ और क्षेत्रीय स्तर के मुद्दों से बाहर निकलकर सबसे पहले देश की एकता, अखण्डता और भारतीय संस्कृति के सरोकार को ध्यान में रखकर ही अपने मत का निश्चय करें। क्योंकि आपका एक मत विश्व पटल पर देश को न केवल सशक्त रूप से स्थापित करेगा बल्कि देश के अंदर भी भारतीय संस्कृति के लिए वरदान साबित होगा।

गौरतलब है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के उत्सव में 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 96.88 करोड़ मतदाता ही भाग्य विधाता हैं। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए सात चरणों में मतदान होगा। बता दें कि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून तक है। यह अमृतकाल है जिसमें 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प सरकार ही नहीं बल्कि हर जन गण को लेना है। ऐसे में हर भारतीय के लिए यह लोकसभा चुनाव संकल्प को सिद्धि में बदलने के मंत्र की तरह है। जहां आपका एक वोट आने वाले समय के लिए भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान और राष्ट्र गौरव के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। इसलिए इस बार का आम चुनाव स्व भारत के संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए एक प्रयोजन भी है। जहां से राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान, आर्थिक महाशक्ति और शक्तिशाली राष्ट्र का भाव पुनर्स्थापित होगा। इसलिए लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग कर आगामी भारत के दिशा और दशा निर्धारण में सहभागी बनें।

# भाजपा 370 पार! कांग्रेस 50 से नीचे?



सुभाष चन्द्र सिंह  
पूर्व सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश



18वीं लोकसभा के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है। करीब 97 करोड़ मतदाताओं के सामने यह अवसर होगा कि वे या तो तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ भाजपानीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को चुनें या कांग्रेसनीत इंडी गठबंधन को। आजादी के बाद यह पहला चुनाव है जिसमें एनडीए तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के प्रति आश्वस्त है। इससे उलट कांग्रेसनीत इंडी अलायंस में आत्मविश्वास की कमी दिख रही है और कांग्रेस का तो बुरा हाल है। इसलिए विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रही है।

**लो**कसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। यह चुनाव 18वीं लोकसभा के लिए होगा। करीब 97 करोड़ मतदाताओं के सामने यह अवसर होगा कि वे या तो तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ भाजपानीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन

<b>कुल सीट 543, बहुमत 272</b>
सात चरण में चुनाव (19 अप्रैल - 1 जून)
मतगणना की तिथि : 04 जून
<b>मतदाता भाग्य विधाता</b>
कुल मतदाता : 96.88 करोड़
पुरुष : 49.7 करोड़
महिला : 47.1 करोड़
ट्रांसजेंडर : 48 हजार

(एनडीए) को चुनें या कांग्रेसनीत इंडी गठबंधन को चुनें। एनडीए का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर रहे हैं, जबकि इंडी गठबंधन का नेतृत्व हालांकि कांग्रेस कर रही है लेकिन इसका कोई नेता नहीं है।

आजादी के बाद यह पहला चुनाव है जिसमें एनडीए तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के प्रति आश्वस्त है। इससे उलट कांग्रेसनीत इंडी अलायंस में आत्मविश्वास की

कमी दिख रही है और कांग्रेस का तो बुरा हाल है। विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रही है। यहां बताते चलें कि देश के राजनीतिक क्षितिज पर नरेन्द्र मोदी के उदय के बाद तीस साल में पहली बार 282 सीटों के साथ भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ 2014 में सत्ता में आयी। दूसरी ओर आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा और उसे मात्र 44 सीटों से संतोष करना पड़ा। उसे लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाने लायक सीटें (55) भी नहीं मिली। प्रसंगवश यह भी बताना जरूरी है कि 2019 के चुनाव में भी भाजपा को 303 सीटों के साथ भारी बहुमत मिला और कांग्रेस को फिर विपक्ष का नेता पद नहीं मिला। उसे 52 सीटों से ही संतोष करना पड़ा।

अब 2024 की बात करते हैं। चुनाव आयोग ने सात चरणों में चुनाव कराने का निर्णय लिया है। चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होंगे और सातवां चरण एक जून को समाप्त होगा। चार जून को मतों की गणना होगी और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में सभी सात चरणों में चुनाव होंगे।

## लोकसभा चुनाव परिणाम 2019

अलायंस	सीट	वोट प्रतिशत
एनडीए	351	38.4
यूपीए	90	26.4

## लोकसभा चुनाव परिणाम 2014

अलायंस	सीट	वोट प्रतिशत
एनडीए	336	38.9
यूपीए	59	23.3

इस बार देश की अधिसंख्य पार्टियां भाजपानीत एनडीए के साथ हैं। कांग्रेसनीत गठबंधन के साथ कम ही दल हैं। यह स्थिति उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक है। बहुत कम ऐसी पार्टियां हैं, जो स्वतंत्र रूप से लड़ रही हैं।

जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख को मिलाकर 6 सीटों का चुनाव पांच चरण में होगा। यानी एक चरण में एक सीट का चुनाव। उधर हिंसाग्रस्त मणिपुर में दो सीटों को चुनाव होना है इसमें अत्यधिक हिंसाग्रस्त एक सीट का चुनाव दो चरणों में होगा। इसलिए चुनाव आयोग ने कुल 543 सीटों के चुनाव के बजाय 544 सीटों पर चुनाव की बात की।

अब आते हैं राजनीतिक समीकरणों पर। देश का राजनीतिक परिदृश्य दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ है एनडीए और दूसरी तरफ है इंडी गठबंधन। एनडीए का मतलब कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं। ऐसा विपक्ष भी मान रहा है। यह चुनाव स्पष्टतया नरेन्द्र मोदी के पक्ष और विरोध पर टिक गया है। यह भी बता दें कि इस बार देश की अधिसंख्य पार्टियां भाजपानीत एनडीए के साथ हैं। कांग्रेसनीत गठबंधन के साथ कम ही दल हैं। यह स्थिति उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक है। बहुत कम ऐसी पार्टियां हैं, जो स्वतंत्र रूप से लड़ रही हैं। अभी तक जो स्थिति सामने आयी है उसमें तमिलनाडु में एआईडीएमके, आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी, तेलंगाना में बीआरएस,

और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस फिलहाल किसी गठबंधन के साथ नहीं हैं।

भारतीय जनता पार्टी विश्वास से लबरेज है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा के लिए 370 पार का नारा दिया है और एनडीए के लिए कहा है कि उसे 400 सीटों से अधिक संख्या में सांसद लेकर आना है। भाजपा को 370 या एनडीए को 400 पार सीटें मिलेंगी अथवा नहीं, यह तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि अपनी जीत के प्रति भाजपा और एनडीए पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं और यही आश्वस्त उनकी जीत की आधारशिला बन सकती है। इससे उलट कांग्रेसनीत इंडी एलायंस में निराशा साफ-साफ दिख रही है। इस तरह की आशा और निराशा सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बयानों में भी दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा और एनडीए के नेता अपने मुद्दों और उपलब्धियों को साथ लेकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो विपक्षी गठबंधन के पास केवल एक मुद्दा है वह है नरेन्द्र मोदी की आलोचना और केवल आलोचना। मोदी की गारंटी यानी गारंटी की गारंटी यह वाक्य जब प्रधानमंत्री दोहराते हैं,

तो जनता में विश्वास का भाव जगता है। लेकिन विपक्ष की ओर से कोई मुद्दे की बात नहीं उठती है और केवल नरेन्द्र मोदी की आलोचना सामने आती है, तो प्रकारान्तर से वह बैकफायर करती है। यानी निशाना उलटा पड़ता है। पार्टियों ने अपने तरकश में हर फेज के लिए कई तीर रखे हैं, लेकिन जो अभी लगता है वह यह है कि प्रधानमंत्री की गारंटी सब पर भारी है।

अब जरा प्रदेशवार राजनैतिक समीकरणों की बात कर लेते हैं। कुछ बड़े प्रदेशों की बात करें, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 80 में से 71, उसके सहयोगी अपना दल को दो सीटें यानी एनडीए को कुल 73 सीटें मिली थीं। सपा को पांच, कांग्रेस को दो सीटें मिली थीं। वहीं बसपा का खाता नहीं खुला था। 2019 में सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था इसके बावजूद भाजपानीत एनडीए को 64 और सपा को 5, बसपा को 10 और कांग्रेस को सिर्फ एक सीट रायबरेली मिली थी। जहां से सोनिया गांधी चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंची थीं। अमेठी से राहुल गांधी खुद चुनाव हार गए थे। केरल की वायनाड सीट से वह जीते थे। 2024 की स्थिति बहुत भिन्न है। बसपा अकेली लड़ रही है। सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। सपा ने अगर अमेठी और रायबरेली को छोड़ दें तो, जो भी 17 सीटें दी हैं उनमें वे 15 सीटें शामिल हैं जहां कांग्रेस की जमीन बिल्कुल अनुवर है। दूसरी ओर भाजपा के साथ अपना दल, सुभासपा, निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल हैं। इनमें सुभासपा और राष्ट्रीय लोकदल 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के साथ थे। विपक्षी गठबंधन में हताशा की स्थिति है। भाजपा ने यहां सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। उसने सुभासपा को एक, रालोद को दो और अपना दल को दो सीटें दी है 75 सीटों पर खुद लड़ रही है। इनमें से संतकबीर नगर सीट पर निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद के पुत्र प्रवीण निषाद 2019 में भाजपा के टिकट पर लड़े थे और

सांसद बने थे। इस बार भी वह वहीं से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ रहे हैं।

अब बिहार पर आते हैं। बिहार में पिछली बार भाजपा, नीतिश की पार्टी जदयू, चिराग पासवान की पार्टी लोकजन शक्ति पार्टी के साथ ही जीतनराम मांझी और उपेन्द्र कुशवाह भी लड़े थे। 40 में से 39 सीटें एनडीए को मिली थीं और एक सीट कांग्रेस को। उस समय कांग्रेस लालू की राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथियों का कुनबा साथ था। इस बार भी कमोबेश यही राजनीतिक समीकरण है। एनडीए को आशा है कि वह पिछला रिकॉर्ड न केवल दोहराएगी बल्कि सभी 40 सीटों पर उसकी विजय होगी। लगे हाथ पश्चिम बंगाल पर भी चर्चा कर लें। यहां भी वहीं स्थिति है। पिछली बार ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने-सामने थे। कांग्रेस और वामपंथी दलों ने संघर्ष को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाए। 42 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस को 22, भाजपा को 18 और कांग्रेस को मात्र 2 सीटें मिली थीं। वामपंथियों का सफाया हो गया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस और वामपंथियों का खाता ही नहीं खुला। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने चुनाव से एन पहले सीएए (नागरिकता संशोधन विधेयक) कानून लागू कर बढ़त हासिल कर ली है। पश्चिम बंगाल का मतुआ समुदाय जिसकी संख्या 1 करोड़ से अधिक है, पूरी तरह भाजपा के साथ आ जाने की संभावना है। सीएए कानून का सबसे ज्यादा लाभ इन्हीं बांग्लादेशी शरणार्थियों को मिलेगा। इनको भारत का नागरिक बनने का अवसर मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी मानकर चल रही है कि उसे 30 से अधिक सीटें मिलेंगी। अगर पड़ोसी असम, त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर की बात करें तो एनडीए काफी आगे है।

पांच और महत्वपूर्ण राज्यों की बात कर लेते हैं। इनमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना का

बड़ा धड़ा मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व में और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस का बड़ा धड़ा आ गया है। विपक्ष में टूटी हुई शिवसेना, टूटी हुई एनसीपी और छिन्न-भिन्न कांग्रेस हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक चौहान और मिलिंद देवड़ा अब एनडीए के साथ हैं। 2019 के चुनाव में एनडीए को 48 में से 41 सीटें मिली थीं। एनडीए को आशा है कि वह अपना पिछला प्रदर्शन न केवल दोहराएगी वरन् पिछला रिकॉर्ड तोड़ भी देगी। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा इस समय अजेय है। इन चारों राज्यों में पिछले बार कांग्रेस को केवल दो सीटें (मद्र में एक और छत्तीसगढ़ में एक) मिली थीं। तब से कांग्रेस और कमजोर हुई है।

**पिछले चुनावों की अगर बात करें तो कई राज्यों में कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला था और 14 ऐसे राज्य थे जहां भारतीय जनता पार्टी को 50 प्रतिशत या उससे अधिक वोट मिले थे और जीतने का उसका स्ट्राइक रेट 85 से 90 प्रतिशत था। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में तो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी।**

पिछले चुनावों की अगर बात करें तो कई राज्यों में कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला था और 14 ऐसे राज्य थे जहां भारतीय जनता पार्टी को 50 प्रतिशत या उससे अधिक वोट मिले थे और जीतने का उसका स्ट्राइक रेट 85 से 90 प्रतिशत था। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में तो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। कई राज्यों में उसे नाम मात्र सीटें मिली थीं। उत्तर प्रदेश में एक, बिहार में एक, पश्चिम बंगाल में एक, ओडिशा में एक, झारखंड में एक, छत्तीसगढ़ में एक, मध्य प्रदेश में एक, तेलंगाना में तीन, महाराष्ट्र में एक सीट से

संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस को सर्वाधिक लाभ दक्षिण के केरल और तमिलनाडु तथा उत्तर भारत में पंजाब से सर्वाधिक सीटें मिले थीं। इन तीनों राज्यों उसे 31 सीटें मिली थीं। इस बार इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएगी, इसमें संदेह है।

अब थोड़ा दक्षिण की बात कर लें। कुल 130 सीटें हैं। कांग्रेस को मात्र 30 सीटें मिली हैं। केरल में 15, तमिलनाडु में 8, तेलंगाना में 3, कर्नाटक में 1 और पुडुचेरी में एक। भाजपा को 29 सीटें मिली हैं। इनमें कर्नाटक में 25 और तेलंगाना में 4 सीटें। राजनैतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बार उसे 30 सीटें मिल जाएं तो बड़ी उपलब्धि होगी। कारण, तमिलनाडु और केरल में वह अपना प्रदर्शन नहीं दोहरा पाएगी। केरल में वामपंथी दलों के कारण घाटा होगा तो तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक इसको हानि पहुंचाएगी। कर्नाटक में इस बार जेडीएस और भाजपा साथ हैं इसलिए यह गठबंधन फायदे में रह सकता है। कांग्रेस और भाजपा के लिए एक मात्र तेलंगाना ऐसा राज्य है जहां दोनों का फायदा हो सकता है। कांग्रेस हाल ही में बीआरएस को हराकर सत्तारूढ़ है। राजनीतिक पंडितों के अनुसार यहां कांग्रेस को पिछली तीन की बजाय सात से आठ सीटें मिल सकती हैं और भाजपा को भी चार की बजाय सात से आठ सीटें मिल सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस बार तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में अच्छी सफलता की उम्मीद है। पिछली बार इन तीनों राज्यों में भाजपा का खाता भी नहीं खुला था। इन तीनों राज्यों से उसको 10 से अधिक सीटों की उम्मीद है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि इस चुनाव में भाजपा और एनडीए पिछली लोकसभा में मिली 353 सीटों से बहुत आगे जा सकते हैं और मुमकिन है कि कांग्रेस को इस बार भी लोकसभा में विपक्ष की सीटें न मिलें। यानी उसके सीटें 55 से कम रह सकती हैं। कांग्रेस के धुर विरोधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनौती भी दे चुकी हैं कि कांग्रेस को पूरे देश में 40 से अधिक सीटें नहीं मिलेंगी।

# आंकड़ों की नजर में महासमर

## आम चुनाव 2024

**प्रथम चरण 19 अप्रैल (21 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश)**

**102 निर्वाचन क्षेत्र** उत्तर प्रदेश की कैराना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर समेत 8 सीटें, अरुणाचल प्रदेश 2, असम 5, बिहार 4, छत्तीसगढ़ 1, मध्य प्रदेश 6, महाराष्ट्र 5, मणिपुर 2, मेघालय 2, मिजोरम 1, नगालैंड 1, राजस्थान 12, सिक्किम 1, तमिलनाडु 39, त्रिपुरा 1, उत्तराखंड 5, पश्चिम बंगाल 3, अंडमान निकोबार 1, जम्मू-कश्मीर 1, लक्षद्वीप 1, पुडुचेरी 1 सीट।  
नामांकन की आखिरी तारीख : 27 मार्च (बिहार- 28 मार्च)।  
नाम वापसी : 30 मार्च (बिहार-2 अप्रैल)।

**दूसरा चरण : 26 अप्रैल (13 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश)**

**89 निर्वाचन क्षेत्र** उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ समेत 8 सीटें, असम 5, बिहार 5, छत्तीसगढ़ 3, कर्नाटक 14, केरल 20, मध्य प्रदेश 7, महाराष्ट्र 8, मणिपुर 1, राजस्थान 13, त्रिपुरा 1, पश्चिम बंगाल 3, जम्मू-कश्मीर 1 सीट।  
नामांकन की आखिरी तारीख : 4 अप्रैल।  
नाम वापसी : 8 अप्रैल।

**तीसरा चरण : 07 मई (12 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश)**

**94 निर्वाचन क्षेत्र** उत्तर प्रदेश की आगरा, एटा, बदायूं, बरेली समेत 10 सीटें, असम 4, बिहार 5, छत्तीसगढ़ 7, गोवा 2, गुजरात 26, कर्नाटक 14, मध्य प्रदेश 8, महाराष्ट्र 11, पश्चिम बंगाल 4, दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव 2, जम्मू-कश्मीर 1 सीट।  
नामांकन की आखिरी तारीख : 19 अप्रैल।  
नाम वापसी : 22 अप्रैल।

**चौथा चरण : 13 मई (10 राज्य /केन्द्र शासित प्रदेश)**

**96 निर्वाचन क्षेत्र** उत्तर प्रदेश की कानपुर, कन्नौज, उन्नाव, हरदोई समेत 13 सीटें, आंध्र प्रदेश 25, बिहार 5, झारखंड 4, मध्य प्रदेश 8, महाराष्ट्र 11, ओडिशा 4, तेलंगाना 17, प. बंगाल 8, जम्मू-कश्मीर 1 सीट।  
नामांकन की आखिरी तारीख : 25 अप्रैल।  
नाम वापसी : 29 अप्रैल।

**पांचवां चरण : 20 मई (8 राज्य /केन्द्र शासित प्रदेश)**

**49 निर्वाचन क्षेत्र** यूपी की लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या समेत 14 सीटें, बिहार 5, झारखंड 3, महाराष्ट्र 13, ओडिशा 5, प. बंगाल 7, जम्मू-कश्मीर 1, लद्दाख 1 सीट।  
नामांकन की आखिरी तारीख : 3 मई।  
नाम वापसी : 6 मई।

**छठा चरण : 25 मई (7 राज्य /केन्द्र शासित प्रदेश)**

**57 निर्वाचन क्षेत्र** उत्तर प्रदेश की प्रयागराज, बस्ती, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ समेत 14 सीटें, बिहार 8, हरियाणा 10, झारखंड 4, ओडिशा 6, पश्चिम बंगाल 8, दिल्ली 7 सीट।  
नामांकन की आखिरी तारीख : 6 मई।  
नाम वापसी : 9 मई।

**सातवां चरण : 01 जून (8 राज्य /केन्द्र शासित प्रदेश)**

**57 निर्वाचन क्षेत्र** उत्तर प्रदेश की वाराणसी, बलिया, गोरखपुर, देवरिया समेत 13 सीटें, बिहार 8, हिमाचल 4, झारखंड 3, ओडिशा 6, पंजाब 13 पश्चिम बंगाल 9, चंडीगढ़ 1 सीट।  
नामांकन की आखिरी तारीख : 14 मई  
नाम वापसी : 17 मई।



# श्रीराममन्दिर से राष्ट्रीय पुनरुत्थान की ओर

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, नागपुर में युगाब्द 5125 फाल्गुन शुक्ल (6-8) (15-17 मार्च 2024) को संपन्न हुई। इसमें पास हुआ प्रस्ताव -

**पौष** शुक्ल द्वादशी, युगाब्द 5125 (22 जनवरी 2024) को श्रीराम जन्मभूमि पर श्रीरामलला के विग्रह की भव्य-दिव्य प्राणप्रतिष्ठा विश्व इतिहास का एक अलौकिक एवं स्वर्णिम पृष्ठ है। हिन्दू समाज के सैकड़ों वर्षों के सतत संघर्ष एवं बलिदान, पूज्य संतों और महापुरुषों के मार्गदर्शन में चले राष्ट्रव्यापी आंदोलन तथा समाज के विभिन्न घटकों के सामूहिक संकल्प के परिणामस्वरूप संघर्षकाल के एक दीर्घ अध्याय का सुखद समाधान हुआ। इस पवित्र दिवस को जीवन में साक्षात् देखने के शुभ अवसर के पीछे शोधकर्ताओं, पुरातत्वविदों, विचारकों, विधिवेत्ताओं, संचार माध्यमों, बलिदानी कारसेवकों सहित आंदोलनरत समस्त हिन्दू समाज तथा शासन-प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान विशेष उल्लेखनीय है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा इस संघर्ष में जीवन अर्पण करने वाले सभी हुतात्माओं के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उपर्युक्त सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है।

श्रीराममन्दिर में अभिन्नित अक्षत वितरण अभियान में समाज के समस्त वर्गों की सक्रिय सहभागिता रही। लाखों रामभक्तों ने सभी नगरों और अधिकांश गांवों में करोड़ों परिवारों से संपर्क किया। 22 जनवरी 2024 को भारत ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण विश्व में अद्भुत आयोजन किये गए। गली-गली और गांव-गांव में स्वप्रेरणा से निकली शोभायात्राओं, घर-घर में आयोजित दीपोत्सवों तथा लहराती भगवा पताकाओं और मंदिरों-धर्मस्थलों में हुए संकीर्तनों आदि के आयोजनों ने समाज में एक नवीन ऊर्जा का संचार किया।

श्री अयोध्याधाम में प्राणप्रतिष्ठा के दिन देश के धार्मिक, राजनैतिक एवं समाज जीवन



के प्रत्येक क्षेत्र के शीर्ष नेतृत्व तथा सभी मत-पंथ-सम्प्रदाय के पूजनीय संतवृंद की गरिमामयी उपस्थिति थी। यह इस बात की द्योतक है कि श्रीराम के आदर्शों के अनुरूप समरस, सुगठित राष्ट्रजीवन खड़ा करने का वातावरण बन गया है। यह भारत के पुनरुत्थान के गौरवशाली अध्याय के प्रारंभ का संकेत भी है। श्री राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से आक्रमणकारियों के शासन और संघर्ष काल में आई आत्मविश्वास की कमी और आत्मविस्मृति से समाज बाहर आ रहा है। सम्पूर्ण समाज हिंदुत्व के भाव से ओतप्रोत होकर अपने 'स्व' को जानने तथा उसके आधार पर जीने के लिए तत्पर हो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का जीवन हमें सामाजिक दायित्वों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए समाज व राष्ट्र के लिए त्याग करने की प्रेरणा देता है। उनकी शासन पद्धति 'रामराज्य' के नाम से विश्व इतिहास में प्रतिष्ठित हुई, जिसके आदर्श सार्वभौमिक व सार्वकालिक हैं। जीवन मूल्यों का क्षरण, मानवीय संवेदनाओं में आई कमी, विस्तारवाद के कारण बढ़ती हिंसा व क्रूरता आदि चुनौतियों का सामना करने हेतु

रामराज्य की संकल्पना सम्पूर्ण विश्व के लिए आज भी अनुकरणीय है।

प्रतिनिधि सभा का यह सुविचारित मत है कि सम्पूर्ण समाज अपने जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के आदर्शों को प्रतिष्ठित करने का संकल्प लें, जिससे राम मंदिर के पुनर्निर्माण का उद्देश्य सार्थक होगा। श्रीराम के जीवन में परिलक्षित त्याग, प्रेम, न्याय, शौर्य, सद्भाव एवं निष्पक्षता आदि धर्म के शाश्वत मूल्यों को आज समाज में पुनः प्रतिष्ठित करना आवश्यक है। सभी प्रकार के परस्पर वैमनस्य और भेदों को समाप्त कर समरसता से युक्त पुरुषार्थी समाज का निर्माण करना ही श्रीराम की वास्तविक आराधना होगी। अ. भा. प्र. सभा समस्त भारतीयों का आह्वान करती है कि बंधुत्व भाव से युक्त, कर्तव्यनिष्ठ, मूल्याधारित और सामाजिक न्याय की सुनिश्चितता करने वाले समर्थ भारत का निर्माण करें, जिसके आधार पर वह एक सर्व कल्याणकारी वैश्विक व्यवस्था का निर्माण करने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर सकेगा।

# राष्ट्र उत्थान की गतिविधियां

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वसुधैव कुटुम्बकम्, राष्ट्र कल्याण, ग्राम विकास, स्वावलम्बन, संस्कारित नागरिक बनाने में स्वयंसेवकों और विभिन्न गतिविधियों के जरिए दिन रात निस्पृह भावना से राष्ट्र उत्थान, भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में प्रभावी होती गतिविधियां निम्नलिखित हैं।

**धर्म जागरण समन्वय :** देश के सभी संयोजक, सह संयोजक और धर्म जागरण समन्वय गतिविधि में काम करने वाले सभी प्रचारकों का 5 दिवसीय अभ्यास वर्ग 24 मई से 28 मई 2023 को संपन्न हुआ। 160 संख्या थी। वर्ग को संबोधन करने के लिए मा. भैयाजी जोशी और सह सरकार्यवाह मा. अरुणकुमार जी उपस्थित थे। जोधपुर प्रांत के सोनाना गांव में 29-30 जुलाई, 2023 को सभी प्रांत प्रमुख एवं संयोजकों की बैठक हुई जिसमें 43 प्रांतों से 147 कार्यकर्ता उपस्थित थे। मा. सरकार्यवाह श्री दत्ताजी व पालक अधिकारी मा. भैयाजी जोशी ने पूर्ण समय रहकर मार्गदर्शन किया। इस वर्ष 241 यात्राएं निकाली। 1535 गांवों में 1,36,995 लाख लोगों से संपर्क हुआ। पश्चिम महाराष्ट्र की जागरण यात्रा में पू. सरसंघचालक जी ने यात्रा का अवलोकन कर खंडोबा देवता का दर्शन भी किया। इसी क्रम में 42 प्रांतों के 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग हुए।

आन्ध्रप्रदेश में 399 हिन्दू सम्मेलनों के माध्यम से 4992 गांवों में से 1,57,205 हिन्दू सम्मिलित हुए। यात्रा में 720 संत एवं समाज के गणमान्य उपस्थित थे।

विदर्भ प्रांत में महिला आयाम का 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग संपन्न हुआ, जिसमें 27 जिलों से 342 सक्रिय महिला कार्यकर्ता उपस्थित थीं।

**मालवा - देवास जिले के खातेगांव तहसील में जामनेर ग्राम के रहवासियों के पूर्वज 40 वर्ष पूर्व रतलाम जिले के आंबा ग्राम से यहां आकर बस गये थे। लगभग 100 वर्ष पूर्व इनके पूर्वजों को मजबूरी में मुसलमान**

बनना पड़ा। अध्ययन में पता चला यह एक घूमंतू जाति है। ये सभी अपनी कुलदेवी मां चामुण्डा (खोड़िया माताजी) का पूजन करते आ रहे हैं। विवाह आदि रस्में भी हिंदू जैसे ही निभाते हैं। संत श्री रामस्वरूप दास जी के कथा कीर्तन सुनकर धीरे-धीरे उनका हिन्दू धर्म में आने का मन बनने लगा। 35 परिवारों के 194 सदस्यों की घर वापसी हुई है।

**काशी - प्रयाग दक्षिण भाग, देवप्रयागम नगर के शान्तिकुन्ज शाखा द्वारा अम्बेडकर बस्ती के सर्वेक्षण के पश्चात धर्मांतरण की समस्या ध्यान में आयी। बस्ती में कुल 12 परिवार मतांतरित हुए थे। बस्ती में धार्मिक उपक्रमों सहित विकास के अनेक उपक्रम चलाये गए। नित्य संपर्क तथा स्नेह बढ़ने से इन परिवारों का फिर हिन्दू धर्म अपनाते का मन बना। अब बस्ती में शंकर जी के मन्दिर का निर्माण भी हुआ है।**

**गो सेवा :** 2023 जुलाई से अक्टूबर तक पूरे देशभर में गोसेवा गतिविधि के कार्य विस्तार और कार्यकर्ता विकास के लक्ष्य को लेकर वर्गों का आयोजन सम्पन्न हुआ। कुल 11 क्षेत्रों के 15 वर्गों में 43 प्रांतों से 1135 कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इन वर्गों में गो सेवा के 11 आयामों का प्रशिक्षण हुआ। इन वर्गों में लगभग 22 कार्यकर्ताओं और 14 वैज्ञानिकों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रांत स्तर पर हुए 88 प्रशिक्षण वर्ग में 2869 प्रशिक्षणार्थी तथा अन्य प्रशिक्षण वर्गों की संख्या 807 रही। उपस्थिति 14502।

**विशेष प्रशिक्षण वर्ग - गो सेवा और ग्राम विकास का पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र का विशेष प्रशिक्षण वर्ग मथुरा में नवंबर 25 से**

28 तक आयोजित हुआ था। 382 कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूरे वर्ग को चार गट में विभाजित कर प्रत्येक गट में दो-दो आयामों का प्रशिक्षण दिया गया। वर्ग में 13 वैज्ञानिक और विशेषज्ञ तथा गो सेवा और ग्राम विकास के 5 अ. भा. अधिकारी उपस्थित रहे। 28 नवंबर को प. पू. सरसंघचालक जी के उद्बोधन से वर्ग सम्पन्न हुआ।

**काशी - चुनार जिले में गो सेवा संगम संपन्न हुआ। 500 गो भक्तों की उपस्थिति के साथ ही माता बहनों का भी सहभाग रहा। समाज में जागरूकता की दृष्टि से गोविज्ञान परीक्षा में 2500 लोगों की सहभागिता रही।**

**ग्रामविकास :** चिंतन बैठक - गत तीन चार दशकों से देश में विभिन्न प्रकार से ग्राम विकास के कार्य हो रहे हैं। प्रांत में सक्षम प्रांत टोली रचना हो और आगामी कार्य योजना को ध्यान में रखकर एक चिंतन बैठक का आयोजन 2023 जून 26 और 27 को नागपुर में मा. सरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबाले जी, आदरणीय भैयाजी जोशी और आदरणीय भागव्याजी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। ग्राम विकास के 7 आयाम के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। ग्राम विकास की अपनी अवधारणा, गांव चयन, मातृशक्ति का सहयोग, किरण - उदय - प्रभात गांव का मापदंड, आयाम में करणीय कार्य, प्रांत टोली, नगरीय कार्य, प्रशिक्षण - ऐसे विषयों में मार्गदर्शन मिला। पश्चात अगस्त माह में संपन्न हुई प्रांत संयोजकों की कार्यशाला में चिंतन बैठक के अनुवर्तन की विस्तृत चर्चा की गई।

**चले गांव की ओर - 7 दिसंबर को**

मालवा प्रांत में ब्रह्मपुर जिला के वनांचल गांव हरदा में आनंद उत्साह का माहौल था। मा. सरकार्यवाह जी ने गांव वालों से संवाद किया। प्रवास में संपूर्ण गांव के सभी आयु वर्ग के 350 से अधिक ग्रामवासियों की सहभागिता रही। माननीय सरकार्यवाह जी के मार्गदर्शन से ग्राम कार्य - राम कार्य है ऐसे भाव जागरण हुआ। इसी प्रकार प. महाराष्ट्र के एक प्रभात गांव शिवे में भी मा. सरकार्यवाह जी का प्रवास हुआ। ग्रामदर्शन, चर्चा, संवाद हुआ।

फरवरी 21 से 25 तक प्रांत टोली का अ. भा. अभ्यास वर्ग देवगिरी प्रांत के सराला बेट में संपन्न हुआ। 271 कार्यकर्ता रहे। पू. सरसंघचालक, मा. सरकार्यवाह, मा. भैयाजी जोशी, मा. भागैयाजी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। पूज्य रामदेव गिरिजीका का सान्निध्य मिला।

**ग्राम संकुल स्वावलम्बी योजना** - 10 से 15 गांव के समूह में स्वावलम्बन की दृष्टि से समाज आधारित कम खर्चे में जरूरतमंद बन्धुओं को रोजगार का अवसर प्रदान करने का प्रयास 2014 से देश के 10 प्रांत का 15 संकुलों में हो रहा है। गत अक्टूबर माह में छत्तीसगढ़ प्रांत के सोनडीह पाली गांव में राष्ट्रीय कार्यशाला संपन्न हुई।

**कर्नाटक उत्तर** - कोप्पळ जिला के हनुमन गांव में संघ के स्वयंसेवक और ग्राम विकास समिति के विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा गांव व्यसनमुक्ति की ओर बढ़ रहा है।

**आंध्र प्रदेश** - कार्यकर्ताओं ने दो दिन भाग लिया। जैविक खेती, स्वास्थ्य, प्रांतीय कार्यशाला में 85 गांव से 108 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। समरसता, स्वावलम्बन विषयों के साथ गोपूजन, भूमि सुपोषण, भजन, प्रभात फेरी का प्रशिक्षण भी दिया गया।

**गुजरात** - नडियाद विभाग के मानली गांव में ग्राम समिति की योजना से 28 महिला बचत गट बने हैं। विषमुक्त खेती के लिए गांव में 200 वर्मी कंपोस्ट बेड बने हैं। साथ ही

कार्बन मुक्त गांव बनाने के लिए 103 बायोगैस प्लांट है। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु गांव में प्रतिवर्ष 2000 से ज्यादा वृक्षारोपण और सुरक्षा की व्यवस्था होती है।

**सौराष्ट्र** - कच्छ विभाग का अटल नगर - चपेरडी ग्राम समिति के द्वारा वृक्षारोपण, जलसंचय, ग्राम स्वच्छता, हनुमान चालीसा केंद्र आदि सामाजिक गतिविधियों से गांव में परिवर्तन हुआ है।

**विदर्भ** - यवतमाल जिला का कृष्णापुर उदय गांव में प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता है।

**मालवा** - बुरहानपुर जिले के आदर्श ग्राम हरदा (जनजातीय बाहुल्य) में लंबे समय से ग्राम विकास एवं स्वावलम्बन का काम हो रहा है। जनसहयोग से पंद्रह वर्ष पहले बना तालाब आज खेती के लिए सहायक है।

**जयपुर** - जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्गों में कुल 166 गांव से 417 कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यकर्ता परिवार भ्रमण कार्यक्रम मे 27 परिवारों से 71 बन्धुओं ने विविध प्रकल्प दर्शन किए तथा अध्ययन किया। सितंबर में संपन्न हुए संत समावेश में 62 संत उपस्थित रहे। पूज्य अदृश्य काडसिद्धेश्वर स्वामी जी का सानिध्य प्राप्त हुआ।

**कुटुम्ब प्रबोधन** : 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का दिव्य ध्येय साकार करने के लिये, विभिन्न प्रयास कुटुम्ब मित्रों के माध्यम से चल रहा है। प्रांतों में कुटुम्बमित्र नियुक्त होते हैं। कुल 1,25,000 है।

**भारत माता पूजन** - कुटुम्ब मित्रों ने अपने तथा संपर्कित परिवारों में 12 से 26 जनवरी तक 'भारत माता पूजन' के कार्यक्रम आयोजित किये।

**समुपदेशन** - तज्ञ व्यक्तियों द्वारा पारिवारिक समस्याएं, वाद-विवाद से उत्पन्न तनाव से राहत देने में सहायता करते हैं।

**समाज के संत सज्जनवृंद के साथ**

**संपर्क** - पूज्य स्वामी गोविन्ददेवगिरी जी, रामकृष्ण मठ के स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, गायत्री परिवार के डॉ. चिन्मय पंड्या जी, वृंदावन के श्री विजय कौशल जी, रा. स्व. संघ. के श्री भैयाजी जोशी जी आदि की उपस्थिति में 'कुटुम्ब - व्यक्तित्व विकास का प्रभावी केन्द्र' विषय पर दिल्ली में 19 मार्च 2023 को चिंतन बैठक संपन्न हुई।

**'श्रेष्ठ संतान - राष्ट्र कल्याण'** - भारत के 44 प्रांतों में अपनी सुविधा अनुसार संवाद, यात्राओं के साथ कुटुम्ब मित्रों के प्रशिक्षण हेतु अभ्यास वर्ग का आयोजन किया जाता है। इस तरह संपूर्ण भारत में 1,25,000 से अधिक कुटुम्ब मित्र सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

**उत्तराखण्ड** - देहरादून में मा. सरकार्यवाह जी की उपस्थिति में दि. 23 दिसंबर 2023 संस्कृति की रक्षा, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी जीवन और नागरिक कर्तव्य बोध इन पांच विषय को लेकर मंगल संवाद कार्यक्रम में महानगर के ज्येष्ठ स्वयंसेवक एवं नगर कार्यकारिणी पर्यन्त 375 स्वयंसेवक परिवारों के 950 सदस्यों ने भाग लिया।

**अवध**- लखनऊ विभाग के कुटुम्ब प्रबोधन गतिविधि द्वारा कुटुम्ब मित्र अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया। आयोजन में कुटुम्ब प्रबोधन गतिविधि की सामान्य जानकारी दी गयी तथा 9 करणीय कार्य का पत्रक भी दिया गया। वर्ग में 44 में से 32 नगरों के 285 कार्यकर्ता उपस्थित थे जिसमें 101 बहनों का समावेश था। वर्तमान में कुल 44 नगरों में 459 कुटुम्ब मित्र कार्य कर रहे हैं। 52 स्थानों पर कुटुम्ब मित्रों के माध्यम से साप्ताहिक/ पाक्षिक सत्संग प्रारम्भ हुए हैं।

**काशी** - 1) काशी महानगर द्वारा दिनांक 24 दिसंबर 2023 को कुटुम्ब मित्र मिलन का आयोजन किया गया। इसमें काशी के 800 कुटुम्ब मित्रों की सपरिवार सहभागिता रही।

कार्यक्रम की अध्यक्षता पूजनीय स्वामी श्री जीतेन्द्रानंद सरस्वती जी ने की। डॉ. रविन्द्र जोशी अखिल भारतीय कुटुम्ब प्रबोधन संयोजक उपस्थित रहे।

2) काशी दक्षिण भाग के केशव नगर के द्वारा मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन दिनांक 23 दिसंबर 2023 को किया गया। 370 मातृशक्ति की सहभागिता रही।

3) प्रयाग दक्षिण भाग के कल्याणी नगर में दिनांक 30 सितम्बर 2023 को कुटुम्ब मित्र सम्मलेन हुआ। 575 कुटुम्ब मित्रों की सहपरिवार सहभागिता रही। इस्कान मंदिर के स्थानीय अध्यक्ष ने सभी को आशीर्वाद प्रदान किया।

### सामाजिक समरसता :

**भगवान वाल्मीकि श्री रामतीर्थ ज्योति यात्रा** - पंजाब एवं उत्तर क्षेत्र के रामलीला समितियों को अमृतसर स्थित भगवान वाल्मीकि श्री रामतीर्थ आश्रम से ज्योति ले जाने का आवाहन किया गया। 112 रामलीलाओं ने इस कार्यक्रम में सहभाग लिया।

**कथावाचक सम्मेलन, मालवा** - नीमच में प्रांत के प्रमुख कथावाचकों का सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में 48 कथावाचक सहभागी हुए। साध्वी ऋतंभरा जी की विशेष उपस्थिति रही।

**समरसता सम्मेलन, आंध्र प्रदेश** - 5 स्थानों पर समरसता सम्मेलन संपन्न हुये।

**गुजरात प्रांत गोष्ठी** - पू. सरसंधवालक जी की उपस्थिति में अनुसूचित समाज से गणमान्य व्यक्तियों की गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में 50 निर्मंत्रित उपस्थित रहे। पू. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी के जीवन पर आयोजित प्रश्न मंजुषा में 936 युवाओं ने भाग लिया।

**महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी उत्थान परिषद्** - यह परिषद् 30 सितंबर को मुंबई में संपन्न हुई। इसमें प्रत्यक्ष नाली में उतरकर स्वच्छता कार्य की रोकथाम, कर्मियों

का पुनर्वास, आवास, आधुनिक मशीनरी के उपयोग तथा अनुसंधान जैसे विभिन्न मुद्दों पर विचार हुआ। राज्य से 480 कर्मचारी प्रतिनिधि, संगठन प्रतिनिधि, विद्यार्थी एवं सरकारी अधिकारी उपस्थित रहे। देश में 156 स्थानों पर स्वच्छता कर्मियों के लिये कार्य चल रहा है।

**आरक्षण बचाव अभियान** - धर्मांतरित हुए पूर्व के अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण देने की मांग का विरोध करने हेतु देशभर में व्यापक अभियान हुआ। कर्नाटक में अनुसूचित जातियों की 3,000 संस्थाएं इस अभियान में सहभागी हुईं। तेलंगाना में 600, उत्तर तमिलनाडु में 172, पंजाब में 124, दक्षिण तमिलनाडु में 80, हरियाणा में 57, गुजरात में 54, हिमाचल में 49, दिल्ली में 48, मेरठ में 25, जम्मू कश्मीर में 18, उत्तराखंड में 4, काशी में 2 संस्थाओं ने इसमें सहभाग लिया। इन 4500 में से अनेक संस्थाओं ने अपने स्वतंत्र ज्ञापन भी दिये।

**समरसता ग्राम** - देशभर में 1419 समस्याग्रस्त क्षेत्र निश्चित किए गये हैं। वहां एक मंदिर, एक शमशान, एक जलस्रोत के लिये एवं विषमता की अन्य समस्याएं सुलझाने के लिये प्रयास किए जा रहे हैं।

**कर्नाटक दक्षिण** - पुत्तूर जिला में सामाजिक समरसता के कार्यकर्ताओं ने गत 2 वर्ष से दीपावली के समय तुडर (तुळू भाषा में तुडर यानी उजाला) कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस वर्ष 'तुडर' कार्यक्रम जिले के 59 मंदिरों में हुए। प्रतिष्ठित मठों के 32 स्वामीजी ने सहभागी होकर सबको आशीर्वाद दिया। जो तथाकथित दलित परिवार ईसाई बने थे ऐसे परिवारों ने भी अपनेपन से सहभाग लिया तथा कृतज्ञता व्यक्त की। अभी 70 प्रतिशत दलित बस्तियों में सकारात्मकता बढ़ी है। कजेकर सेवा बस्ती में गत 3 वर्षों के प्रयत्न के कारण गांव वालों ने मिलकर 40 वर्ष पुराने जर्जर सत्यसारमणि मंदिर का जीर्णोद्धार किया।

इससे गांव में समरसता का वातावरण बना तथा अनेक वर्षों से प्रलंबित जमीनी कागजात का हस्तांतरण हो पाया।

**पर्यावरण संरक्षण** - संगठनात्मक संरचना - 45 प्रान्तों में से 44 में संयोजक नियुक्त हैं। कुल प्रान्त टोली कार्यकर्ता 578 हैं। विभाग संयोजक 220, जिला संयोजक 918 तथा महानगर संयोजक 200 हैं।

**कार्यशाला एवं प्रशिक्षण** - 1) SIP (Social Internship Program) 75 विश्वविद्यालयों के 4000 से अधिक विद्यार्थियों का प्रतिमाह ऑनलाइन प्रशिक्षण पिछले तीन वर्षों से चल रहा है। 100 विद्यार्थी पर्यावरण प्रहरी बनकर सक्रिय कार्य कर रहे हैं।

2) रक्षा विभाग में एक कार्यशाला आयोजित की गयी। लगभग 300 सेना अधिकारियों एवं परिवार के सदस्यों के समक्ष इको ब्रिक्स बनाने, कचरा विभाजित करने, रसोई के कचरे से खाद बनाने तथा बायोएंजाइम बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। 350 विद्यालयों में इको ब्रिक की कार्यशालाएं आयोजित की गयीं।

3) दो कार्यशालाएं आयोजित की गईं। 270 पुलिसकर्मियों के साथ तथा प्रदेश के NSS के लगभग 210 जिला प्रमुखों के साथ। इसमें राष्ट्रीय सेवा योजना की राज्य प्रमुख श्रीमती नीता बाजपेयी की गरिमामयी उपस्थिति रही।

**राष्ट्रीय कार्यक्रम** : 1) राष्ट्रीय छात्र पर्यावरण प्रतियोगिता (NSPC - 2023) पर्यावरण पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन ऑनलाइन किया गया। जिसमें 103 देशों के 72,000 शिक्षण संस्थानों से 6 लाख 60 हजार विद्यार्थियों ने भाग लिया।

2) 'एक पेड़ देश के नाम' अभियान के अंतर्गत देश में लगभग 575 सघन वन सामाजिक सहभागिता से लगाये गये। राजस्थान में 300 से अधिक सघन वन अभी तक लगे हैं। कुल 35,514 घरों में बीजारोपण कर पीथे लगाये गए।



आशुतोष कुमार पाण्डेय  
पत्रकार

## एक देश-एक चुनाव

लोकतांत्रिक सरकारों का मूल स्तंभ है चुनाव प्रणाली। इसलिए आजादी के बाद हुए लोकसभा और विधानसभाओं के 400 से अधिक चुनावों में देश ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मानदंड स्थापित किये हैं। लेकिन इन सात दशकों में चुनाव की रूपरेखा, समय और किफायती चुनाव पर व्यापक विमर्श भी साथ-साथ जारी रहा। उसी का क्रम है एक देश एक चुनाव की रिपोर्ट।

एक देश एक चुनाव पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 18,626 पृष्ठों वाली इस रिपोर्ट में समिति ने लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की है। उसके बाद देश में एक चुनाव की व्यवहार्यता और इसे लागू करने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श का दौर शुरू हो गया। वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट में पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का समर्थन है। पैनल की सिफारिशों के अनुसार, इसके बाद 100 दिनों के भीतर समकालिक स्थानीय निकाय चुनाव होने चाहिए। समिति में शामिल प्रमुख उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों में से नौ ने एक साथ चुनाव का समर्थन किया, जबकि तीन ने इससे संबंधित चिंताएं या आपत्तियां उठाईं।

बता दें कि दो सितंबर, 2023 को अपने गठन के बाद से 191 दिनों में विशेषज्ञों के

साथ व्यापक परामर्श और अनुसंधान हुआ। जिसमें 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए, इसमें से 32 ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया। यानी 80 फीसदी ने एक साथ चुनाव कराने की सहमति जतायी। ऐसे में यह रिपोर्ट आम रायशुमारी से तैयार की गयी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में विधि विशेषज्ञ के रूप में चार पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और प्रमुख उच्च न्यायालयों के बारह पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, चार पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्तों, आठ राज्य निर्वाचन आयुक्तों और विधि आयोग के अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया था। भारत निर्वाचन आयोग से भी विचार मांगे गए थे। इसके अलावा सीआईआई, फिक्की, एसोचैम जैसे शीर्ष व्यापारिक संगठनों और वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों से भी पृथक चुनावों के आर्थिक नतीजों पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए परामर्श किया गया था। हालांकि पैनल की अनुशंसा के मुताबिक ऐसा सिंक्रनाइजेशन, सिद्धांत रूप में,

2029 की शुरुआत में हो सकता है।

गौरतलब है कि वर्ष 1951-52 से वर्ष 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन अधिकांशतः साथ-साथ कराए गए थे। इसके बाद यह चक्र टूट गया और अब, निर्वाचन लगभग प्रत्येक वर्ष और एक वर्ष के भीतर विभिन्न समय पर भी आयोजित किए जाते हैं, जिसका परिणाम सरकार और अन्य हितधारकों द्वारा बहुत अधिक व्यय, ऐसे निर्वाचनों में लगाए गए सुरक्षा बलों और अन्य निर्वाचन अधिकारियों की उनकी महत्वपूर्ण रूप से लंबी कालावधि के लिए अपने मूल कर्तव्यों से भिन्न अन्यत्र तैनाती, आदर्श आचार संहिता, आदि के लंबी अवधि तक लागू रहने के कारण, विकास कार्य में दीर्घ अवधियों के लिए व्यवधान होता है। भारत के विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों में सुधार पर अपनी 170 वीं रिपोर्ट में यह संकेत किया है कि - प्रत्येक वर्ष और बिना उपयुक्त समय के निर्वाचनों के चक्र का अंत किया जाना चाहिए। इसी तरह कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए साथ-साथ निर्वाचन आयोजित करने की साध्यता पर दिसम्बर 2015 में प्रस्तुत अपनी 79वीं रिपोर्ट में भी इस मामले की जांच की है और दो चरणों में साथ-साथ निर्वाचन आयोजित करने की एक वैकल्पिक और व्यवहार्य विधि की सिफारिश की है; अतः अब पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रीय हित में साथ-साथ निर्वाचन कराना वांछनीय है, भारत सरकार साथ-साथ निर्वाचनों के मुद्दे की जांच करने और देश में एक साथ निर्वाचन आयोजित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति और उसकी रिपोर्ट उसी का परिणाम है।

इस रिपोर्ट पर दिल्ली विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉ. अश्विनी महाजन का कहना है कि बार-बार चुनाव होते रहने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। अलग-अलग समय पर



**वर्तमान में प्रति वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव और किसी न किसी राज्य में लगभग हर तीसरे महीने वाले नगर निगम या पंचायत चुनाव को देखते हुए उपरोक्त आशंकाओं और बाधाओं के बाद भी एक देश एक चुनाव प्रासंगिक और प्रगतिशील विचार है। जिससे देश के महत्वपूर्ण संसाधनों की बचत होगी।**

चुनाव होते रहने से बार-बार आचार संहिता के कारण विकास कार्य में रुकावट आती है। सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षाबलों को बार-बार चुनावी ड्यूटी पर जाना पड़ता है। ऐसे में अगर मोदी सरकार इसे लागू करने में सफल होती है तो इससे देश को बहुत फायदा होगा।

हालांकि शुरुआत में एक देश एक चुनाव पर अमल में अधिक जनसंख्या के कारण कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं। यथा लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने और उसके कुछ महीने बाद नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव के कारण एक लंबा समय चुनाव प्रक्रिया की भेंट चढ़ सकता है। क्योंकि अभी जब लगभग दो महीने का समय

लोकसभा चुनाव में लग सकता है, तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के एक साथ होने से यह समय करीब चार महीने तक पहुंच सकता है। इस पर भी विचार करने की जरूरत है। इसके अलावा त्रिशंकु लोकसभा एवं विधानसभा की स्थिति में बड़े पैमाने पर दल बदल और बार-बार सरकारों को गिरने के परिणामस्वरूप ही तो 1967 के बाद ही मध्यावधि चुनाव की स्थिति बनी। इसलिए वही पैटर्न कहीं फिर न बन जाये इसलिए इस पर गंभीर मंथन जरूरी है। इसी तरह एक राष्ट्र एक चुनाव के कार्यान्वयन के रास्ते में कानूनी चुनौतियां भी हैं जिसके निदान के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ सकता है। और अंत में ईवीएम, वीवीपैट सहित लॉजिस्टिक्स जैसे उपकरणों की खरीद, जनशक्ति, मतदान कर्मियों और सुरक्षाबलों की तैनाती एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था करने के लिए पहले से व्यापक तैयारी और संसाधनों की चुनौतियों से भी पार पाना होगा। हालांकि वर्तमान में प्रति वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव और किसी न किसी राज्य में लगभग हर तीसरे महीने वाले नगर निगम या पंचायत चुनाव को देखते हुए उपरोक्त आशंकाओं और बाधाओं के बाद भी एक देश एक चुनाव प्रासंगिक और प्रगतिशील विचार है। जिससे देश के महत्वपूर्ण संसाधनों की बचत होगी। ■

# सीएए : पीड़ित मानवता के लिए वरदान



पंकज जगन्नाथ जयस्वाल  
ब्लॉगर एवं शिक्षाविद



**ना**गरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 यानी सीएए के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। इससे अब सीएए कानून एक साथ देशभर में लागू हो गया है। गौरतलब है कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 (सीएए) तीन निर्दिष्ट देशों यथा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में छह अल्पसंख्यक समुदायों (हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) के व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है, जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए (31 दिसंबर 2014 तक) हैं। यह मौजूदा कानूनी प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं करता है, जो किसी भी वर्ग, पंथ, धर्म या समूह के विदेशियों को पंजीकरण या देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति है। ऐसे लोगों को नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले न्यूनतम कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। वहीं इसके लागू होने से उपरोक्त तीन देशों से आए 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अब आसानी से नागरिकता मिल जाएगी। इस तरह व्यापक

सीएए कानून किसी की नागरिकता का हनन नहीं करेगा बल्कि कई दशकों से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में पीड़ित और शोषित हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के व्यक्तियों को एक कानूनी अधिकार दे रहा है। इसके द्वारा 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके इस समुदाय के व्यक्ति अब भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी यह पीड़ित मानवता के कल्याणार्थ वरदान है।

दृष्टिकोण में सीएए मानवता के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि इन 6 अल्पसंख्यकों के शोषण का सिलसिला इन तीन देशों में किस प्रकार से कई दशकों से होता रहा है यह किसी से छिपा नहीं है।

**सीएए क्यों जरूरी :** प्राचीन इतिहास पर नजर डालें, तो जब भारत अखण्ड था उस समय राष्ट्र की सीमा का विस्तार काफी बड़े भूक्षेत्र तक था। अब के पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे कई देश भारत के अभिन्न हिस्सा थे। कालांतर में अंग्रेजों की बांटों और राज करो की कुटिल नीति के चलते भारत के एक भाग को अलग कर एक देश के रूप में मान्यता दे दी। ऐसे में अपने ही भाई बंधु अलग होकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में

अल्पसंख्यक के रूप में अभिशप्त जीवन जीने को मजबूर हो गये। इसलिए वे 6 समुदाय भारतीय सभ्यता और संस्कृति के तहत पहचान के उत्तराधिकारी हैं, और हमारा दायित्व है कि उनकी पहचान को संरक्षित कर उनके घोर कष्ट को दूर करें। सही अर्थों में सीएए का यही अर्थ और प्रतिबद्धता भी है। इसलिए अब वर्तमान नेतृत्व नागरिकता विधेयक के माध्यम से अपने पड़ोस में सताए गए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को राहत प्रदान करेगा।

**देर से किया गया प्रायश्चित :** भारतीय संस्कृति के मानवीय दर्शन की दृष्टि से इस कानून की आवश्यकता आजादी के तुरंत बाद थी। जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में इस्लामी

चरमपंथ को मिली छूट से चिंतित हिंदू अपनी जान बचाने के लिए भारत आए, तो उन्हें तिरस्कार और तकलीफों का सामना करना पड़ा। एक तरफ हत्या, बलात्कार, अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन का खतरा था, वहीं दूसरी तरफ भारत में लंबी कानूनी प्रक्रिया या शिविरों में कैद की चिंता। इन देशों में उत्पीड़न के शिकार हिंदू, बौद्ध और सिख विभाजन नहीं चाहते थे। उन पर विभाजन थोपा गया। पाकिस्तान में 1947 से और बांग्लादेश में 1971 से जो नरसंहार हो रहा है, वह विभाजन की त्रासदी का उदाहरण है। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए 2019) इस गलती का देर से किया गया प्रायश्चित्त है। हालांकि विभाजन के दौरान लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया गया, लेकिन कई हिंदू पाकिस्तान में ही रह गए। इस हिंदू समूह में कई दलित भी थे। उसके बाद जो लोग आये उन्हें काफी मानसिक और शारीरिक कष्ट झेलने पड़े। वे घुसपैठिए नहीं शरणार्थी हैं। धार्मिक उत्पीड़न के कारण कुछ लोग अपना देश छोड़कर भारत में शरण मांग रहे हैं। ऐसे में भारत को अपने लोगों को भारतीय नागरिकता देने में मानवता के प्रत्येक उद्देश्य की ही रक्षा होगी? अगर हिंदू भारत नहीं आएंगे, तो कहां जाएंगे? भारत वह देश है जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं। परिणामस्वरूप, अन्य देशों के हिंदू या विभिन्न धर्मों के व्यक्ति भारत में अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश भारत की सीमा के करीब तीन देश हैं, जहां मुस्लिम बहुमत है। यहां रहने वाले हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई सभी अल्पसंख्यक हैं। यदि इन राष्ट्रों में उन पर अत्याचार किया जाएगा, तो वे कहां भागेंगे? चाहे वे कहीं भी हों, उनकी जड़ें केवल भारतीय हैं।



**इन देशों में अल्पसंख्यकों का शोषण :** विभाजन के समय पाकिस्तान में हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय की कुल जनसंख्या की लगभग 15.16 प्रतिशत थी, जो 75 वर्षों के बाद घटकर लगभग 1.5 से 2 प्रतिशत रह गयी। शोध के अनुसार, 2002 में पाकिस्तान में करीब 40,000 सिख थे; आज, उनकी संख्या 8000 से भी कम है। इसी तरह कई और अल्पसंख्यक हैं जिनकी आबादी 2 हजार से भी कम है। 1947 में, हिंदू और बौद्ध अनुयायी बांग्लादेश (1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान) की कुल आबादी का लगभग 28 प्रतिशत थी, जबकि आज वे 8 फीसदी से भी कम हैं। 1970 के दशक में अफगानिस्तान में अफगान हिंदुओं और सिखों की संख्या 7 लाख से अधिक थी, लेकिन 1990 में गृह युद्ध के बाद से इसमें लगातार गिरावट आई और वर्तमान में यह 3000 से कम हो गयी है।

अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश, विशेषकर पाकिस्तान में तो आए दिन उपरोक्त 6 अल्पसंख्यक समुदायों के साथ भीषण अत्याचार और शोषण की खबरें आती हैं। जबरन धर्म परिवर्तन, बेटियों के साथ बलात्कार आदि घटानाएं तो इस समुदाय के साथ आम हैं। क्योंकि पाकिस्तान की कानून व्यवस्था और न्याय

प्रणाली का वहां के कट्टरपंथियों को कोई डर नहीं है। पाकिस्तान में हर महीने जबरन धर्म परिवर्तन की दर्जनों घटनाएं घटती हैं। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में भी अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिखों, यहूदियों और ईसाई धर्म की आबादी के पलायन की बात स्वीकारी गई है।

इसलिए यदि भारत धार्मिक उत्पीड़न के चलते उपरोक्त पीड़ितों को आश्रय देता है, तो इससे किसी भी भारतीय को कोई नुकसान नहीं होगा। सवाल यह भी उठता है कि अगर इन तीन इस्लामिक देशों के छह समुदाय भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, तो उन देशों के मुसलमान क्यों नहीं? इसका सीधा उत्तर यह है कि ये तीनों देश मान्यता प्राप्त इस्लामिक देश हैं, इसलिए वहां धार्मिक आधार पर मुस्लिम प्रभुत्व का कोई भी सुझाव बेतुका है। इस तरह नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को लागू करने का निर्णय मनुष्यता को आस्तादित करने वाला है। यानी सीएए उन पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याणार्थ किसी वरदान से कम नहीं है, जिनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर रही है। इसलिए अब सीएए से उन पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मानजनक जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ■



# भारतीय संस्कृति को स्थापित करता एक फिल्मोत्सव



डॉ. यशार्थ मंजुल

फिल्म अध्ययन विभाग, महात्मा गांधी  
अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

**भा**रत विश्व गुरु केवल आर्थिक नजरिए से ही नहीं बन सकता, क्योंकि इसके कई आयाम हैं। इन्हीं में से एक है भारतीय सिनेमा, जिसका महत्वपूर्ण योगदान है। ये बात विवेक अग्निहोत्री ने भारतीय चित्र साधना द्वारा 23-25 फरवरी, 2024 को पंचकुला, हरियाणा में आयोजित चित्र भारती फिल्मोत्सव के पांचवें संस्करण के उद्घाटन सत्र में कही। गौरतलब है कि 2016 में शुरू हुआ ये फिल्मोत्सव धीरे-धीरे एक बड़े फलक पर आकार ले रहा है। शायद ही वैश्विक स्तर पर कोई फिल्मोत्सव हो जो बिना सरकारी सहयोग के शुचिता के साथ इतने कम समय में समाज में अपनी प्रासंगिकता को स्थापित किया है। यह संभव हुआ जन भागीदारी से। फिल्मोत्सव में भारत की सभी भाषाओं की फिल्मों की सहभागिता हुई। शामिल 663 फिल्मों में से 19 भाषाओं में 133 फिल्में प्रदर्शित की गईं। कथानक, बिंब, शैली, शिल्प और रूपक के स्तर पर नये अर्थ रचती अधिकतर फिल्में भारत के महानगरों से नहीं, बल्कि छोटे शहरों और गांवों से आई थीं। ये विकेंद्रीकरण की उस खूबसूरती को दर्शाती है, जिसमें एक कला रूप को रचने के लिए अब एलिटिस्म (elitism) की चौहद्दी में रहना आवश्यक नहीं। बहु भाषीय होना भारत की एक शक्ति है इसका सफल उदाहरण यह फिल्मोत्सव है। कार्यक्रम में भारत के लगभग सभी प्रदेशों से युवा फिल्मकार मौजूद थे।

फिल्मकारों ने तीन दिन सिनेमाई कला में भारतीय विचार को कैसे बढ़ावा मिले, इसके लिए सिनेमा और संस्कृति के विभिन्न घटकों के आदान-प्रदान व समन्वय पर गंभीर विमर्श भी किया। गौरतलब है कि सिनेमाई कला में भारतीय विचार को बढ़ावा देने के औचित्य से आयोजित चित्रभारती फिल्मोत्सव युवा फिल्मकारों की एक नर्सरी की रूप में उभर रहा है। यह ऐसे फिल्मकारों को रोपने में सहायक है, जिनमें कहानी कहने की क्षमता के साथ ही संसाधनों की उपयोगिता का प्रबंधन भी हो। भारतीय विचार को बढ़ावा देने के औचित्य के क्रम में ऐसी फिल्में निर्मित करना है, जिसमें

**सिनेमाई कला में भारतीय विचार को बढ़ावा देने के औचित्य से आयोजित चित्रभारती फिल्मोत्सव, युवा फिल्मकारों की एक नर्सरी के रूप में उभर रहा है। यह ऐसे फिल्मकारों को रोपने में सहायक है, जिनमें कहानी कहने की क्षमता के साथ ही संसाधनों की उपयोगिता का प्रबंधन भी हो।**

मूलतः भारतीयता को बढ़ावा मिले। फिल्मोत्सव के 'भारत की बात' नामक सत्र में अनंत विजय कहते हैं कि अस्सी के दशक की फिल्में सोशलिस्ट कांटेंट के निमित्त पूंजीवाद के टूल से बनती थीं। ये दोनों ही विचार भारत के नहीं हैं। ये आयातित हैं। ऐसे में इन फिल्मों में भारतीय गांवों का चित्रण यूरोपियन दृष्टि से किया जाता रहा। चित्रभारती फिल्मोत्सव इसी यूरोपियन दृष्टि के विपरीत सिनेमा में भारतीय दृष्टि देने का एक प्रयास है। कार्यक्रम में हरियाणा और पंजाब की लोक कलाओं पर भी कई सत्र आयोजित हुए। ऐसे में चित्रभारती फिल्मोत्सव महानगरों में हो रहे आडम्बर

युक्त और द्वंद्व भरे आयोजनों के विपरीत यह सिनेमा के आयोजन को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव की तरह प्रस्तुत करता है, जो लोककलाओं के शिल्प को दर्शक दीर्घा के समक्ष प्रस्तुत करता है। यह आयोजन शॉर्ट फिल्मों पर केंद्रित था। जिसमें कथा और वृत्तचित्र आदि की विभिन्न श्रेणियां थीं। इन फिल्मों में प्रस्तुत शिल्प के जरिए कथानक की व्याख्या कई स्तरों पर समावेशित रहती है। इसलिए ये फिल्में नवोदित कलाकारों और विद्यार्थियों के लिए सीखने का अच्छा माध्यम हैं। इससे कला के छात्रों को भारतीय सिनेमा में चल रहे प्रयोगों की जानकारी भी मिलती है।

इस आयोजन के दूसरे मास्टर क्लास "भारतीय सिनेमा में भारतीयता" में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह डॉ. मनमोहन वैद्य ने कहा कि सिनेमा में पश्चिम की बजाय भारत को भारत की ही दृष्टि से देखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत 'एकम् सत् विप्रा बहुधा वदन्ति' की परंपरा का देश है। इसे ही भारतीय सिनेमा को प्रस्तुत करना चाहिए। गौरतलब है कि कला और राष्ट्र में चेतना का अंतर्संबंध है। दीन दयाल उपाध्याय ने चिति को व्याख्यायित करते हुए कहा है कि प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक विशेष प्रकृति होती है, जो ऐतिहासिक अथवा भौगोलिक कारणों का परिणाम नहीं, अपितु जन्मजात है। इसे चिति कहते हैं। राष्ट्रों का उत्थान-पतन चिति के अनुकूल अथवा प्रतिकूल व्यवहार पर निर्भर करता है। इस चिति के निर्माण में हजारों वर्ष का समय लगता है। ये एक सतत प्रक्रिया है। सूचना के इस वर्तमान दौर में इसके निर्माण में कहानी एवं कला की भूमिका और बढ़ जाती है। सिनेमा एक संपूर्ण कला है। यह विभिन्न कलाओं को अपने भीतर आत्मसात किए हुए है। इसलिए इसकी भूमिका अन्य कलाओं से कहीं अधिक है। ■



प्रो. (डॉ.) अनिल कुमार निगम  
वरिष्ठ पत्रकार

एक मजदूर से राजनेता तक का सफर तय करने वाला शाहजहां शेख आज कुख्यात खलनायक बन चुका है। संदेशखाली पश्चिम बंगाल की वह जगह है, जहां पर इस खलनायक की तूती बोलती थी। उस शख्स पर लोगों की जमीन हड़पने से लेकर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं। हैरानी की बात यह है कि पश्चिम बंगाल की मुखिया भी एक महिला ममता बनर्जी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ममता ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की जगह मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की। इसी के चलते आज संदेशखाली सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर सुर्खियों में आ गया।

सवाल यह है कि महिलाओं के साथ हैवानियत करने और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे शाहजहां को गिरफ्तार और पार्टी से निष्कासित करने में इतना अधिक समय क्यों जाया किया गया? स्थिति अत्यंत गंभीर होने पर उच्च न्यायालय तक को हस्तक्षेप करना पड़ा। क्या बंगाल पुलिस ने खलनायक को सिर्फ इसलिए नहीं गिरफ्तार किया, क्योंकि वह तृणमूल कांग्रेस का नेता था और ऐसा करने से पार्टी की बदनामी होती? यह ऐसे सवाल हैं जिसका



## संदेशखाली का संदेश चुनाव में नहीं जाएगा खाली!

महिलाओं के साथ हैवानियत करने और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे शाहजहां को गिरफ्तार और पार्टी से निष्कासित करने में इतना अधिक समय क्यों जाया किया गया? स्थिति अत्यंत गंभीर होने पर उच्च न्यायालय तक को हस्तक्षेप करना पड़ा? क्या पश्चिम बंगाल पुलिस ने खलनायक को सिर्फ इसलिए नहीं गिरफ्तार किया, क्योंकि वह तृणमूल कांग्रेस का नेता था

जवाब होने वाले चुनाव में ममता बनर्जी से अवश्य पूछना चाहिए।

खलनायक शाहजहां संदेशखाली में कहां से आया, ये कोई नहीं जानता। वर्ष 2001 में मछली पालन केंद्र में मजदूर था। उसने सब्जी भी बेची। फिर ईट-भट्टे पर काम करने लगा। यहीं उसने मजदूरों की यूनियन बनाई। फिर सीपीएम से जुड़ गया।

सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन में वामदलों की जमीन खिसकी तो समय की नजाकत को भांपते हुए वह वर्ष 2012 में तत्कालीन महासचिव मुकुल

रॉय और उत्तर 24 परगना जिले के ताकतवर नेता ज्योतिप्रिय मलिक के सहारे पार्टी से जुड़ गया। जिस राशन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय शाहजहां को खोज रहा है, उसी केस में मलिक जेल में हैं। ध्यातव्य है कि शाहजहां के पास सैकड़ों मछली पालन केंद्र, ईट भट्टे, सैकड़ों एकड़ जमीन है। वह लगभग 4 हजार करोड़ की संपत्ति का मालिक है।

शाहजहां शेख ने देखते ही देखते अपार संपत्ति जुटा ली और संदेशखाली में खौफ का दूसरा नाम बन गया। उस

पर पश्चिम बंगाल के राशन वितरण घोटाले में 10 हजार करोड़ रुपये का गबन करने का आरोप है। ईडी ने इसी मामले में सबसे पहले बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को गिरफ्तार किया था। हजारों करोड़ रुपये के राशन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने 5 जनवरी को पश्चिम बंगाल में 15 ठिकानों पर छापा मारा था। इसके बाद जब ईडी की टीम उसको पकड़ने संदेशखाली पहुंची तो उस पर ही हमला हो गया। टीम नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेशखाली गांव में शेख शाहजहां और शंकर अध्यक्ष के घर भी रेड डालने गई थी। इस दौरान उन पर टीएमसी समर्थकों ने जानलेवा हमला किया था। इसमें तीन अधिकारी घायल हो गए थे।

राज्य चुनाव आयोग में दायर हलफनामे के अनुसार, शाहजहां शेख के पास करोड़ों की संपत्ति है। इसमें 17 वाहन, 2.5 करोड़ रुपये के सोने के गहने और 14 एकड़ से अधिक जमीन शामिल है। इन सबकी कुल कीमत अनुमानतः चार हजार करोड़ रुपये है। इसके अलावा, उसी हलफनामे में बताया गया है कि उसके बैंक खाते में 1.92 करोड़ रुपये जमा हैं। आज संदेशखाली में जो कुछ हुआ, वह किसी से छिपा नहीं है। संदेशखाली में टीएमसी नेता शाहजहां ने जिस तरीके से वहां की महिलाओं के साथ दुष्कर्म एवं यौन शोषण किया और उनकी जमीनें हड़पीं और दीदी उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जगह उसे लगातार बचाने की कोशिश करती रहीं, उससे संदेशखाली आज राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन गया है।

दिलचस्प बात यह है कि मीडिया



**ममता अपने किले को येन केन प्रकारेण बचाने के लिए सभी दांव पेंच अपना रही हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर उन्होंने बांग्लादेश से माइग्रेट कर आए मुस्लिम मतदाताओं के सामने एक बार फिर तुष्टीकरण का पासा फेंक दिया है।**

और विपक्षी दलों के दबाव के चलते टीएमसी को न केवल शाहजहां को गिरफ्तार करना पड़ा बल्कि उसे पार्टी से भी निष्कासित करना पड़ा। आज संदेशखाली के मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दल ममता बनर्जी पर लगातार हमलावर हैं। अब दीदी को यह समझ में आ रहा है कि उनकी जमीन खिसक रही है। वह अच्छी तरह से जानती हैं कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश में असली संघर्ष बीजेपी के साथ होने वाला है। तृणमूल कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनावों में कुल 22 सीटें जीती थीं। उसका वोट शेयर 43 प्रतिशत था। हालांकि पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनावों के लिए 16 सांसदों को रिपीट

किया है। यही नहीं, कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में दो सीटें जीती थीं। उसका वोट प्रतिशत 5.6 रहा। जबकि भाजपा 18 सीटें जीती थीं और वोट शेयर 40.6 फीसदी रहा। चूंकि बीजेपी की सीटें और वोट परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है, इसलिए ममता अपने किले को येन केन प्रकारेण बचाने के लिए सभी दांव पेंच अपना रही हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर उन्होंने बांग्लादेश से माइग्रेट कर आए मुस्लिम मतदाताओं के सामने एक बार फिर तुष्टीकरण का पासा फेंक दिया है।

ममता ने कहा है कि वह बंगाल में सीएए और एनआरसी को लागू नहीं होने देंगी। इसके अलावा जिन लोगों के आधार कार्ड बने हुए हैं, उनको स्कैन नहीं होने देंगी। उनकी इस घोषणा का क्या असर होगा और चुनाव में कौन किसको पटकनी देगा, यह तो समय बताएगा लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि ममता इस समय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं और तृणमूल को बचाने के लिए सभी सियासी दांव पेंच अपना रही हैं। ■

# मठ-मंदिरों पर कसता सरकारी शिकंजा



डॉ. मनमोहन सिंह शिशौदिया  
शिक्षक, भौतिकी विज्ञान विभाग  
गौतमबुद्ध विवि, ग्रेटर नोएडा



**भा**रत के मठ-मंदिर मात्र पूजा-अर्चना तथा भेंट अर्पित करने के स्थान न होकर समाज की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक चेतना तथा ज्ञान-विज्ञान के केंद्र रहे हैं। जैसे हृदय, रक्त के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य अपशिष्ट बाहर निकालकर शरीर का पोषण करता है, उसी तरह मठ-मंदिर भी समाज में ज्ञान-विज्ञान एवं संस्कृति के प्रचार-प्रसार तथा अज्ञान एवं कुरीतियों से संघर्ष के केंद्र रहे हैं। मठ-मंदिर ऐसे संस्कार केंद्र रहे हैं जो मानव जीवन की वास्तविकता, व्यापकता एवं सार्थकता का अहसास तो कराते ही हैं, अहं ब्रह्मास्मि एवं धर्मो रक्षति रक्षितः जैसी अदृश्य, अव्यक्त एवं अनंत क्षमताओं का बोध कराने के माध्यम भी बनते हैं। सनातन की आशा, विश्वास, श्रद्धा एवं शक्ति के स्रोत होने के साथ ही ये उसकी संस्कारशाला तथा विशिष्ट वास्तुकला, चित्रकला, प्रौद्योगिकी एवं सर्वसाधारण के इकट्ठा होकर उत्सव मनाने तथा अन्य सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा देने वाले प्रेरणा स्थल रहे हैं। भारतवर्ष के अनेक राजा मंदिर में प्रतिष्ठित इष्ट देव को ही वास्तविक शासक मानकर उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। मेवाड़ के महाराणा श्री एकलिंग महादेव को मेवाड़ का शासक और स्वयं को उनका प्रतिनिधि अथवा दीवान मानते थे।

भारत के मठ-मंदिर मात्र पूजा-अर्चना तथा भेंट अर्पित करने के स्थान न होकर समाज की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक चेतना तथा ज्ञान-विज्ञान के केंद्र रहे हैं। जैसे हृदय, रक्त के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य अपशिष्ट बाहर निकालकर शरीर का पोषण करता है, उसी तरह मठ-मंदिर भी समाज में ज्ञान-विज्ञान एवं संस्कृति के प्रचार-प्रसार तथा अज्ञान एवं कुरीतियों से संघर्ष के केंद्र रहे हैं।

अंग्रेजों के भारतीय सत्ता पर काबिज होने से पहले, भारत के मठ-मंदिरों का प्रबंधन भारत के स्थानीय समुदायों द्वारा किया जाता था। उस कालखंड में विदेशी आक्रांताओं ने भारतीय समाज में हीन भावना जगाने, बलात धर्मांतरण के लिए विवश करने तथा आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए भारत के अनेक मठ-मंदिरों को न केवल लूटा बल्कि उन्हें ध्वस्त करने एवं उनका स्वरूप बदलने का प्रयास भी किया। अयोध्या, मथुरा एवं काशी के साथ ही कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर, गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर, कर्नाटक का हम्पी मंदिर, मदुरई (तमिलनाडु) का मीनाक्षी मंदिर, जौनपुर (उ०प्र०) का अटाला मंदिर इस बर्बरता और लूटमार के आज भी गवाह हैं। अरब यात्री अल-बरुनी के सोमनाथ मंदिर की भव्यता एवं समृद्धि के वर्णन से प्रेरित हो महमूद गजनवी ने 8 जनवरी 1026 को

सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर वहां की विशाल संपत्ति को तो लूटा ही, वहाँ आए पुरुष श्रद्धालुओं एवं पुजारियों को मौत के घाट उतारा और महिलाओं तथा बच्चियों को दासता के नरक में झोंक दिया। इसी तरह भारत पर शासन करते हुए अंग्रेजों ने मठ-मंदिरों की संपत्ति को अपने नियंत्रण में लेने के लिए कई कानून बनाए। वर्ष 1925 में अंग्रेजों द्वारा लाए गए, 'Madras Religious and Charitable Endowments Act 1925' का जब मुस्लिमों और ईसाइयों ने विरोध किया तो उन्हें इससे बाहर रखकर इसका नाम बदलकर 'Madras Hindu Religious and Endowments Act 1927' करते हुए इसे केवल हिंदुओं के लिए लागू कर दिया गया। वर्ष 1947 में भारत के आजाद होने के बाद भारतीय समाज को विश्वास था कि सरदार

वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुआ सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भारत के मठ-मंदिरों की स्वायत्तता का मार्ग प्रशस्त करेगा। परंतु इसके उलट यहां की सरकारें मठ-मंदिरों का संचालन येन केन प्रकारेण अपने हाथों में लेने का खेल खेलती रहीं जो आज भी भली-भांति जारी है।

हालिया प्रकरण है कर्नाटक सरकार द्वारा 'कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती (संशोधन) विधेयक 2024' का पारित किया जाना। इसकी परतें खंगालने पर पता लगता है कि, 'कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1997 (Karnataka Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1997)' को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा एक रिट अपील के कारण रद्द कर दिया गया था। तत्पश्चात उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगाते हुए अधिनियम के सेक्शन 25 को छोड़कर शेष अधिनियम को लागू करने की अनुमति दे दी गई थी। तत्पश्चात कर्नाटक सरकार ने निर्णय के प्रभावों के परीक्षण हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया और समिति की सिफारिशों के आधार पर इस अधिनियम को बदलने का निर्णय लिया। ज्ञात हो कि कर्नाटक सरकार का मुजरई विभाग लगभग 35000 मठ-मंदिरों का संचालन करता है। वर्ष 2011 में संशोधित अधिनियम में अधिसूचित संस्थानों एवं सरकार से प्राप्त अनुदान से राज्य धार्मिक परिषद को सार्वजनिक पूल निधि (COMMON POOL FUND) बनाने के लिए अधिकृत किया गया। अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि जिन अधिसूचित संस्थानों की कुल आय 10 लाख रुपये से अधिक है उनसे उनकी शुद्ध आय का 10 प्रतिशत तथा जिनकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक परंतु 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है, उनकी शुद्ध आय का 5 प्रतिशत इस निधि में जमा होगा। हाल ही में कर्नाटक सरकार 'कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और

धर्मार्थ बंदोबस्ती (संशोधन) विधेयक 2024' लेकर आई जिसे पहली बार वहां के विधानमंडल ने खारिज कर दिया। परंतु हठधर्मिता दिखाते हुए कर्नाटक सरकार ने इसे तब पास करा लिया जब विपक्षी दल सदन का बहिष्कार कर रहे थे। हालांकि इसमें विपक्ष की मिलीभगत से भी इंकार नहीं किया जा सकता, विशेषकर जब वो ही 2011 के अधिनियम के निर्माता रहे हों। इस कानून के अनुसार जिन मंदिरों की सालाना आमदनी 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये के बीच है, उनसे पांच प्रतिशत और एक करोड़ रुपये से अधिक आमदनी वाले मंदिरों से 10 प्रतिशत रकम इकट्ठा कर राज्य धार्मिक परिषद द्वारा प्रशासित सार्वजनिक पूल रकम में रखने की व्यवस्था है। सरकार का तर्क है कि जमा धन का उपयोग पुजारियों तथा अन्य कर्मचारियों के परिवारों

**अब संविधान का सम्मान करते हुए दलों की दलदल से निकलकर सभी सरकारों को धार्मिक स्थलों के नियंत्रण संबंधी कानूनों को स्वयं खत्म करना चाहिए। समानता एवं स्वतंत्रता केवल संविधान के पृष्ठों तक ही सीमित न होकर यथार्थ में परिलक्षित होनी चाहिए। आशा है सरकारों की मठ-मंदिरों पर आधिपत्य की गजनी-लिप्सा का अंत शीघ्र होगा।**

(लगभग 40000) के जीवन बीमा, मृत्यु लाभ, छात्रवृत्ति आदि के लिए किया जाएगा। साथ ही सरकार नियंत्रित जिन मंदिरों की सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है उनके रख रखाव में भी इसका उपयोग किया जाएगा। न केवल कर्नाटक अपितु अन्य सरकारें भी मठ-मंदिरों के बेहतर प्रबंधन के नाम पर नादिरशाही कानून बनाने की आदी रही हैं। धार्मिक स्वतंत्रता तथा धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता संबंधी भारतीय संविधान के 25वें एवं 26वें अनुच्छेद की पृष्ठभूमि में स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि यह व्यवस्था केवल मठ-मंदिरों के

लिए ही क्यों? मठ-मंदिरों के प्रबंधन में ही सरकारी दखलंदाजी क्यों? आवश्यकता आज देश में इन विसंगतियों को और बढ़ाने नहीं अपितु उनकी जड़ों में मूठ डालने की है। देश में जब एकसमान आचार संहिता पर बहस चल रही हो, उस समय ऐसे कानून बनाना समाज में भ्रम अवश्य पैदा करता है। क्या अब वह समय नहीं आ गया है जब संविधान के अनुरूप सभी मजहबों को समान अधिकार एवं धार्मिक स्वतंत्रता देते हुए सरकार मठ-मंदिरों को अपने चंगुल से अविलंब मुक्त करे? प्रशासनिक दक्षता एवं बेहतर प्रबंधन की आड़ में हड़पे गए मठ-मंदिर आज भी उपेक्षा, बदहाली और कुप्रबंधन के शिकार हैं। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु सरकार के अनुसार वर्ष 1997-2018 (25 वर्ष) में प्रदेश के मठ-मंदिरों से लगभग 1000 मूर्तियों की चोरी हुई, जिनमें से मात्र 18 को ही पुनः प्राप्त किया जा सका। आंकड़ों के अनुसार देश के एक लाख से अधिक मंदिरों पर जहां सरकारों का पूर्ण नियंत्रण है, अन्य मजहबों के पूजा स्थल सरकारी नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त हैं। हालांकि भारतीय समाज के प्रयासों से इस दिशा में कुछ सराहनीय परिणाम आने अवश्य आरंभ हुए हैं। जैसे वर्ष 2021 में उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमनोत्री, तथा गंगोत्री सहित 51 मंदिरों को राज्य सरकार ने अपने नियंत्रण से मुक्त कर दिया। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी अयोध्या नगर निगम को मंदिरों एवं अन्य धार्मिक संस्थानों से इस आधार पर हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स आदि न वसूलने के लिए कहा है कि ये मंदिर, धर्मशालाएं एवं परोपकारी संस्थान जनसेवा एवं पुण्य का कार्य कर रहे हैं। अब संविधान का सम्मान करते हुए दलों की दलदल से निकलकर सभी सरकारों को धार्मिक स्थलों के नियंत्रण संबंधी कानूनों को स्वयं खत्म करना चाहिए। समानता एवं स्वतंत्रता केवल संविधान के पृष्ठों तक ही सीमित न होकर यथार्थ में परिलक्षित होनी चाहिए। आशा है सरकारों की मठ-मंदिरों पर आधिपत्य की गजनी-लिप्सा का अंत शीघ्र होगा। ■

# घरेलू सजावट का देशी केंद्र “चौखट”

ढेर सारी चुनौतियों एवं असफलताओं को हराकर एक प्रेरणास्रोत सक्सेस स्टोरी है गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) की उद्यमी प्राची भाटिया की। उनकी उल्लेखनीय यात्रा दृढ़ संकल्प, समन्वय और सपनों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रस्तुत है ‘चौखट होम प्राइवेट लिमिटेड’ नामक एक मशहूर होम डेकोर व्यवसाय की संस्थापिका प्राची भाटिया से बातचीत का संपादित अंश-

**प्रा**ची की कहानी केवल उद्यमशीलता के बारे में ही नहीं है बल्कि यह वित्तीय बाधाओं और सामाजिक अवरोधों से मुक्त होने का संघर्ष भी है। जो अक्सर किसी के जीवन और उद्देश्य का मार्ग तय करते हैं। उनकी कड़ी मेहनत, नवप्रवर्तन और मजबूत इरादे महिला सशक्तिकरण का प्रमाण है। गौरतलब है कि चौखट, घरेलू साज-सज्जा में विशेषज्ञता वाला, एक अनूठा और सफल उद्यम है। रचनात्मकता और डिजाइन इसकी विशेषता है। सार रूप में चौखट घरेलू साज-सज्जा और सजावट के एक अनूठे केंद्र का दूसरा नाम है। उनके उत्पाद न केवल घरों में सुंदरता और स्टाइल में वृद्धि करते हैं, बल्कि राष्ट्र की परंपरा और भारतीयता के वाहक भी हैं।

इस यात्रा की शुरुआत पर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मेरे मन में कभी भी यह बिजनेस नहीं था। क्योंकि मैं मध्यमवर्गीय परिवार में पली-बढ़ी हूँ, जहां हर कोई जॉब करना चाहता है। इसलिए मैं भी इस मानसिकता के साथ बड़ी हुई कि आपको अच्छे अंक लाकर, अच्छे कॉलेज में जाना होगा और नौकरी करनी है। ताकि आय का एक निश्चित स्रोत हो। व्यवसाय में आर्थिक उतार-चढ़ाव के कारण यह भावना मध्यम वर्ग में आम है। इसी विचार से पोषित होने के चलते मेरी भी शुरुआत एक्सपोर्ट हाउस में जॉब से हुई। जहां मुझे 12 घंटे से अधिक काम करना पड़ता था। इसके बाद मैंने उस जॉब को छोड़कर एक दूसरी बहुराष्ट्रीय कंपनी, जो गुडगांव में ही थी,



वहां ज्वाइन किया। वह भी अधिक दिन तक नहीं चली। फिर मैंने तीसरी जॉब पर स्विच किया। यहां डिजाइन हाउस में वरिष्ठ डिजाइनर के रूप में नियुक्ति हुई। यहां अनुभव और भी बुरा रहा। इस दौरान जॉब के बुरे अनुभव से मेरे दिमाग में एक उद्यमी बनने के लिए कुछ हलचल शुरू हो चुकी है। इंटीरियर डिजाइन और घर की साज-सज्जा में रुझान लगातार बढ़ता ही जा रहा था। साहस और प्रतिबद्धता के चलते इंतजार की घड़ी खत्म हुई और आखिरकार वह दिन आ ही गया 13 सितंबर 2018 गणेश चतुर्थी को, जब मैंने ‘चौखट’ को धरातल पर उतारा।

बातचीत के क्रम में प्राची ने इस यूनीक नाम के महत्व और उस तर्क के बारे में बताया- मैं हमेशा से एक भारतीय नाम रखना चाहती थी। इसलिए मैंने यह नाम चुना है। हालांकि, मैंने

कई और नाम शॉर्टलिस्ट किए थे, जैसे - लालटेन, चारपाई, बक्सा आदि। एक प्रकार से चौखट लोगों को अपने घर को अलग तरह से अनुभव करने के लिए नवीन रूप प्रदान करता है? चौखट वह उद्योग है जो जरूरतों और चाहतों पर काम करता है। बता दें कि हर घर का अपना सार होता है और वह समय के साथ बदलता रहता है। इसलिए हम कपड़े की तरह घर का लुक भी बदलते हैं। उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मैं इसे इनोवेटिव बनाती हूँ। मैं अपने लोगों और उपभोक्ताओं से इस बारे में बात करती हूँ कि यह एक बहुत सस्ता, किफायती और सुंदर उत्पाद है। लेकिन अगर आप इसे सौंदर्य की दृष्टि से देखें, तो यह बहुत सरल और बुनियादी होता है।

पिछले एक-दो दशक से चलन है कि यदि आप अच्छी वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो वह

ब्रांडेड होगी और महंगी भी। विशेषकर कुशन, सोफा, टेबल, परदे और ट्रे जैसी वस्तुओं के भाव तो आसमान छूते हैं। यह इसलिए है कि क्योंकि एक आम धारणा है कि अच्छा वही होगा, जो आयातित और महंगा होगा। लेकिन यह अर्धसत्य है, जबकि आपकी प्राथमिकता में अच्छा और सस्ता होना चाहिए। चौखट में, मैंने इसी सोच को सबसे ज्यादा महत्व देते हुए चीजों को सुंदर और किफायती रखा ताकि ग्राहक अपनी इच्छाओं से समझौते किये बिना भी जरूरत के अनुसार खरीद सकें। विशेषकर मध्यवर्ग, जिसकी जरूरतों और इच्छाओं में अक्सर द्वंद्व रहता है। इस तरह 'चौखट' लागत, गुणवत्ता, सौंदर्य और संतुलन का दूसरा नाम है।

चौखट के शुरुआती उत्पाद के डिजाइन की बात करें, तो वह थी टोकरी। इस प्रोडक्ट की सफलता चौखट के लिए वरदान सिद्ध हुई। उसका नाम है चौखट बुलबुल शूट बास्केट। जब आप अमेज़न पर जाते हैं और चौखट टाइप करते ही सर्च में सुझाव के रूप में ट्रे आपको मिल जाएगी। टॉप सर्च सुझाव बॉक्स में सजावट के लिए यही एक सुनहरी ट्रे है। कभी-कभी जब मैं मुड़कर चौखट के बारे में सोचती हूँ, तो इसकी सरलता में सफलता की डोर मिलती है।

इसी तरह चौखट के अन्य उत्पादों की बात करें, तो गद्दे, पर्दे, चटाई, बर्तन और कई तरह के फर्नीचर सब आपको चौखट में मिल जाएगा। अब यह पूरा स्टार्टअप उस सपने से मेल खाता है, जिसे मैं साकार करना चाहती थी। अपनी यात्रा के इस सफर में धीरे-धीरे प्रोडक्ट की गुणवत्ता और किफायती दाम अब चौखट की पहचान बन चुके हैं। हालांकि समय के साथ इसमें अब बहुत बदलाव आया है। अब प्रोडक्ट के साथ इसके पैकेजिंग पर भी ध्यान दे रही हूँ।

एक लाइन में कहें, तो चौखट घर की जरूरतों और खूबसूरती के लिए एक संपूर्ण पैकेज है। यह सिर्फ एक होम डेकोर कंपनी ही नहीं है, बल्कि राष्ट्र के लिए भारतीय विचारों



का दैनिक दिनचर्या की वस्तुओं के लिए एक विचार है। यदि आप किफायती घर की साज-सज्जा, उपहार देने के बारे में सोच रहे हैं, तो निश्चित ही आपकी पहली पसंद चौखट होगी। इस समय चौखट में लगभग 99 उत्पाद हैं। इनमें से अधिकतर वस्तुएं सोने की तरह चमकती हैं। जिससे घर की खूबसूरती में चार चांद लग जाता है। शुरुआत में मेरी टीम काफी छोटी थी। लेकिन बाद में व्यापार का विस्तार होने पर अन्य टीमों को आउटसोर्स किया। क्योंकि एक बिजनेस में सिर्फ उत्पाद ही सबकुछ नहीं है। कच्चे उत्पाद के अलावा कोटिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट जैसे पहलू भी काफी मायने रखते हैं। इसके अलावा ग्राहक

प्रबंधन, सोशल मीडिया हैंडलिंग, शिपिंग, वित्त आदि को भी मैनेज करना होता है। आज के बाजार में सबसे जरूरी है प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए नवाचार को जारी रखना। और हम ये कार्य लगातार करते आ रहे हैं। इसलिए चौखट बाजार में मौजूद अन्य ब्रांडों से अलग है। पहले हम ग्राहक और उनकी समस्याओं को उनसे बात कर समझते हैं। फिर एक ब्रांड के रूप में वे हमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, उस पर विचार कर प्रोडक्ट तैयार करते हैं। इस तरह चौखट हर दिन सफलता की सीढ़ियां चढ़कर भारतीय बाजारों में भारतीयता को स्थापित कर रहा है। ■

# कुलांचे भर रही अर्थव्यवस्था

भारत में वित्तीय वर्ष 2023-24 की तृतीय तिमाही में अनुमानों से कहीं अधिक वृद्धि दर हासिल करने के पीछे दरअसल हाल ही के समय में आर्थिक क्षेत्र के साथ-साथ सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तन की भी मुख्य भूमिका है।



प्रह्लाद सबनानी

सेनानिवृत्त उप महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक



**वि**त्तीय वर्ष 2023-24 की तृतीय तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर ने भारत सहित विश्व के समस्त आर्थिक विश्लेषकों को चौंका दिया है। इस दौरान, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हासिल हुई है जबकि प्रथम तिमाही के दौरान वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत एवं द्वितीय तिमाही के दौरान 7.6 प्रतिशत की रही थी। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान वृद्धि दर 4.4 प्रतिशत रही थी। साथ ही, क्रेडिट रेटिंग संस्थान इकरा ने इस वर्ष तृतीय तिमाही में 6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान एवं भारतीय स्टेट बैंक ने भी 6.9 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान जताया था। कुल मिलाकर, लगभग समस्त वित्तीय संस्थानों के अनुमानों को झुठलाते हुए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 8.4 प्रतिशत की रही है।

हम सभी के लिए हर्ष का विषय तो यह है कि विनिर्माण इकाइयों की वृद्धि दर 4.8 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 की तृतीय तिमाही में 11.6 प्रतिशत हो गई है तथा निर्माण के क्षेत्र में वृद्धि दर 9.5 प्रतिशत की रही है। साथ ही, खनन के क्षेत्र में वृद्धि

दर 1.4 प्रतिशत से बढ़कर 7.5 प्रतिशत की रही है। यह तीनों ही क्षेत्र रोजगार सृजन के क्षेत्र माने जाते हैं। अतः देश में अब रोजगार के नए अवसर भी निर्मित हो रहे हैं। विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों में वृद्धि दर आकर्षक रही है। कृषि का क्षेत्र जरूर, विपरीत मानसून एवं अल नीनो के प्रभाव के चलते, विपरीत रूप से प्रभावित हुआ है एवं कृषि के क्षेत्र में वृद्धि दर 0.2 प्रतिशत ऋणात्मक रही है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2019-20 से लेकर 2022-23 तक कृषि के क्षेत्र में औसत वृद्धि दर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक की रही है। परंतु, प्रकृति के आगे तो किसी की चलती नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद के विशेष रूप से उद्योग क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर के आंकड़ों को देखकर तो अब यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि भारत आगे आने वाले वर्षों में

10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की विकास दर हासिल करने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है एवं अगले लगभग 4 साल के अंदर ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, वर्तमान में भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथ ही, भारतीय शेयर बाजार भी बाजार पूंजीकरण के मामले में वर्तमान में विश्व में चौथे स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। क्योंकि, भारत में आर्थिक विकास की तीव्र गति को देखते हुए विदेशी निवेशक एवं विदेशी निवेश संस्थान, दोनों ही भारतीय पूंजी बाजार में अपने निवेश को निश्चित ही बढ़ाएंगे।

भारत में वित्तीय वर्ष 2023-24 की तृतीय तिमाही में अनुमानों से कहीं अधिक वृद्धि दर हासिल करने के पीछे दरअसल हाल ही के समय में आर्थिक क्षेत्र के साथ-साथ सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तन भी मुख्य भूमिका निभाते नजर आ



रहे हैं, इस ओर सामान्यतः विदेशी अर्थशास्त्रियों एवं वित्तीय संस्थानों का ध्यान शायद नहीं जा रहा है। हाल ही के समय में भारत में अब विभिन्न त्यौहार अत्यधिक उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। इन त्यौहारों के मौसम एवं शादियों के मौसम में भारतीय परिवारों, विशेष रूप से मध्यम वर्गीय एवं उच्च वर्गीय परिवारों के खर्च में अपार वृद्धि हो रही है। इस खर्च का पूरा पैसा भारतीय अर्थव्यवस्था में आ रहा है, जिससे आर्थिक वृद्धि दर में तेजी दिखाई देने लगी है। वर्ष 2023 में दीपावली त्यौहार के दौरान लगभग 4 लाख करोड़ रुपये की राशि भारतीय परिवारों द्वारा खर्च की गई थी। शादियों के दौरान भारतीय परिवारों द्वारा अतिरिक्त खर्च किया जाना भी एक अतिरिक्त विशेषता है, अन्य देशों में शादियों के दौरान इस प्रकार के खर्च नहीं होते हैं। दूसरे, भारत में हाल ही के समय में धार्मिक पर्यटन में अपार वृद्धि देखने में आई है, क्योंकि इन क्षेत्रों की आधारभूत संरचना में आमूल चूल सुधार हुआ है। पर्यटन के बढ़ने से न केवल रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित हो रहे हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी अपार बल मिल रहा है। अयोध्या, वाराणसी, उज्जैन, हरिद्वार, वृंदावन आदि धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों की अपार वृद्धि दिखाई दे रही है। अयोध्या में तो प्रभु श्रीराम के मंदिर के शिलान्यास के बाद से लगातार औसतन प्रतिदिन 1 लाख से अधिक पर्यटक अयोध्या पहुंच रहे हैं। इससे न केवल स्थानीय, बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिल रहा है।

हालांकि केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र में लगातार किए जा रहे सुधारों के चलते एवं पूंजीगत खर्च में लगातार की जा रही बढ़ोतरी से भी भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार द्वारा 10 लाख करोड़ रुपये की राशि इस मद पर खर्च की गई है जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस मद पर 7.5 लाख करोड़



**अब भारतीयों को आर्थिक क्षेत्र में लगातार अच्छे समाचार मिलने लगे हैं, क्योंकि भारत रोजाना किसी न किसी क्षेत्र में नित नए रिकॉर्ड बनाता दिखाई दे रहा है। इस प्रकार, अब भारतीयों को नित नए रिकॉर्ड सुनने की आदत बना लेनी चाहिए।**

रुपये की राशि खर्च की गई थी। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में पूंजीगत खर्च की राशि को बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। दूसरे, भारत में कर (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष) के संग्रहण में भी सुधार दिखाई दे रहा है। कर ढांचे को आसान बनाकर सम्बंधित नियमों के अनुपालन में सुधार कर, कर संग्रहण में 20 प्रतिशत के आसपास की वृद्धि हासिल की गई है। देश में अनौपचारिक क्षेत्र भी तेजी से औपचारिक क्षेत्र में बदल रहा है, इससे कर संग्रहण के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी औपचारिक क्षेत्र में अधिक निर्मित हो रहे हैं तथा विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलते दिखाई दे रहे हैं।

विशेष रूप से कोरोना महामारी के खंड काल के बाद से (वित्तीय वर्ष 2022 से वित्तीय

वर्ष 2024 के बीच) भारत में औसत प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में 38,257 रुपये की वृद्धि दर्ज हुई है एवं अब यह प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपये को पार कर गई है। इस दौरान प्रति व्यक्ति बचत एवं पूंजी निर्माण में भी वृद्धि दृष्टिगोचर है। भारत में सकल बचत की दर वित्तीय वर्ष 2023 में 30.2 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024 में 32.3 प्रतिशत से अधिक रहने की सम्भावना व्यक्त की गई है, जो वित्तीय वर्ष 2014 के बाद से सबसे अधिक दर रहने वाली है। अब देश में पूंजी का उपयोग अधिक दक्षता के साथ किया जा रहा है। जिससे क्रमिक पूंजी-उत्पाद अनुपात में पर्याप्त सुधार हुआ है। यह अनुपात दर्शाता है कि अतिरिक्त उत्पाद के निर्माण में कितनी अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होने वाली है। वित्तीय वर्ष 2012 में क्रमिक पूंजी-उत्पाद अनुपात 7.5 प्रतिशत था जो वित्तीय वर्ष 2023 में घटकर 4.4 प्रतिशत हो गया है। अतः देश में वर्तमान बचत दर को देखते हुए भारत आसानी से 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की विकास दर हासिल कर सकता है। कुल मिलाकर, अब भारतीयों को आर्थिक क्षेत्र में लगातार अच्छे समाचार मिलने लगे हैं, क्योंकि भारत रोजाना किसी न किसी क्षेत्र में नित नए रिकॉर्ड बनाता दिखाई दे रहा है। इस प्रकार, अब भारतीयों को नित नए रिकॉर्ड सुनने की आदत बना लेनी चाहिए। ■



## प्रभु श्रीराम और नदियां



रमन कान्त  
रिवर मैन ऑफ इण्डिया  
अध्यक्ष : भारतीय नदी परिषद

जब पूरा देश राममय है, तो ऐसे में भारत को प्रभु राम के जीवन की प्रत्येक सीख को अपनाते हुए भारत की सम्पूर्ण समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। अगर हम नदियों के साथ अपने आचरण, व्यवहार व सरोकार को राम राज्य की दृष्टि से समझना चाहते हैं, तो पहले हमें प्रभु राम के नदियों के संदर्भ में आचरण व विचारों को भी समझना होगा।

**श्री** राम एक शरीर रूपी धर्म हैं, ऐसा धर्म जो मर्यादित भी है और संयमित भी। प्रभु राम की शिक्षा जीवन व व्यवस्था के प्रत्येक हिस्से को व्यवस्थित करने के लिए संपूर्ण माध्यम है। जब पूरा देश राममय है, तो ऐसे में भारत को प्रभु राम के जीवन की प्रत्येक सीख को अपनाते हुए भारत की सम्पूर्ण समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। अगर हम नदियों के साथ अपने आचरण, व्यवहार व सरोकार को राम

राज्य की दृष्टि से समझना चाहते हैं, तो पहले हमें प्रभु राम के नदियों के संदर्भ में आचरण व विचारों को भी समझना होगा। प्रभु राम का उनके जन्म, शिक्षा, वन गमन से लेकर जल समाधि द्वारा महाप्रयाण करने तक के सफर में विभिन्न नदियों के साथ जो व्यवहार व सरोकार दिखता है वह वर्तमान समय में भारतीय व्यवस्था व समाज को सटीक शिक्षा देने वाला है।

ऋग्वेद की जैमिनीय संहिता में प्रभु राम के

जन्म स्थान का उल्लेख सरयू नदी से निश्चित दूरी व दिशा के सम्बन्ध में उल्लेख मिलता है। इसके पश्चात महर्षि वशिष्ठ के आश्रम माउंट आबू में शिक्षा प्राप्त करने के दौरान स्कन्द पुराण में बनास व उसकी सहायक नदियों के साथ सरोकार मिलता है। जनकपुरी जाते हुए भी दूधमती व बागमती नदियों का उल्लेख मिलता है। इसके पश्चात प्रभु राम के वन गमन के समय अयोध्या से बाहर तमसा नदी को पार करके श्रृंगवेरपुर में गंगा नदी के उस

पार कुरई गांव पहुंचने का जिक्र आता है, जिसको केवट संवाद के रूप में भी जानते हैं। यहां प्रभु राम व केवट दोनों का गंगा मां से संवाद भी होता है। जब केवट अपनी नाव में प्रभु राम को बैठा लेते हैं, तो वो गंगा से प्रार्थना करते हैं कि मेरी नाव में प्रभु राम बैठे हैं कृपया अपनी रफ्तार को मंद कीजिये। यहां से आगे प्रयाग में यमुना नदी को पार करके प्रभु राम चित्रकूट पहुंचते हैं। यहीं पर राजा भरत उनको मनाने के लिए आते हैं और उनकी चरण पादुका लेकर लौट जाते हैं। यहां से आगे प्रभु राम दंडकारण्य वन में प्रवेश करते हैं जोकि वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य के सतना जनपद में है। प्रभु राम का वन गमन यहीं से प्रारम्भ होता है। दंडकारण्य वन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगना व ओडिशा राज्यों में अर्थात् महानदी से गोदावरी नदी के मध्य विस्तारित है। यहीं गोदावरी नदी के किनारे भद्राचलम में प्रभु राम और माता सीता का प्राचीन मंदिर स्थित है। यहां से प्रभु राम गोदावरी नदी के किनारे स्थापित पंचवटी पहुंचे। पंचवटी का सुंदर वर्णन वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में है।

पंचवटी तक तो प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण जी साथ थे, लेकिन पंचवटी से जानकी जी का रावण द्वारा हरण कर लेने के बाद यहां से आगे प्रभु राम व लक्ष्मण जानकी जी की खोज में आगे बढ़ते हैं। यहां के बाद प्रभु राम कावेरी व तुंगभद्रा नदी को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। केरल में बहने वाली तुंगभद्रा नदी को पम्पा के नाम से भी जाना जाता है। इसी पम्पा नदी को पार करके प्रभु राम माता सबरी के आश्रम पहुंचते हैं। यहीं पर प्राचीन सबरीमाला मंदिर भी स्थित है। यहां से आगे मलय पर्वत व चन्दन वनों से होते हुए प्रभु राम हनुमान जी तथा सुग्रीव से मिलते हैं और फिर हनुमान जी के गुरु मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं। फिर प्रभु राम वानर सेना बनाकर रामेश्वरम पहुंचते हैं और शिवलिंग स्थापित करके नल व नील को रामसेतु निर्माण का आदेश देते हैं। पुल पार



**शरीर को नियमित प्रभावी बनाने में महती भूमिका धमनियों में संचालित होने वाले रक्त की होती है। अगर यह रक्त किसी कारण से दूषित होगा तो शरीर का संचालन बहुत अधिक समय तक संभव ही नहीं होगा। कुछ इसी प्रकार भारत भूमि को एक शरीर के रूप में, यहां बहती नदी को धमनियों की तरह और नदियों में बहते जल को रक्त के रूप में देख सकते हैं। वर्तमान में धमनी रूपी नदियों में रक्त रूपी बहने वाला पानी प्रदूषित हो चुका है। यही कारण है कि भारत की नदियां बहुत अच्छे हालातों में नहीं हैं। इन परिस्थितियों में शरीर रूपी भारत अपनी चेतना को साधते हुए अपना धर्म निभा सकता है। हालांकि इस सन्दर्भ में भारत सरकार से लेकर बहुत से सामाजिक संगठन व कार्यकर्ता नदी सुधार के कार्यों में गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में देश राममय है और भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मनाकर अमृत काल की यात्रा पर निकल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के समक्ष आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर वाटर विजन 2047 का लक्ष्य तय किया है। अब जब लम्बी अवधि के बाद 22 जनवरी को भव्य श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है तो प्रभु राम के नदियों से किये गए मधुर व सम्मानित व्यवहार को अपनी सीख में उतारना होगा। भारत की नदियों का जल जब शुद्ध होगा तो यह जीवन और उससे संबंधित गतिविधियां समृद्ध होंगी।**

श्रीलंका में रावणवध करके माता जानकी को अयोध्या लाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जन्म से लेकर वन गमन पूरा करके अयोध्या वापस आने तक छोटी-बड़ी करीब दो दर्जन नदियों के

संपर्क में आते हैं। इस दौरान प्रभु राम प्रत्येक नदी के साथ आदर भाव रखते हुए उसको पूजते हैं।

यह सर्वविदित तथ्य है कि पृथ्वी पर सभी प्राणियों की रचना पंच महाभूतों से ही होती है। इस शरीर के बेहतर संचालन हेतु जहां उसकी संरचना के सभी अंगों की आवश्यकता है वहीं उसमें चेतना की सर्वाधिक उपयोगी व महत्वपूर्ण भूमिका है, जोकि शरीर संचालन का महत्वपूर्ण तत्व है। इस शरीर को नियमित प्रभावी बनाने में महती भूमिका धमनियों में संचालित होने वाले रक्त की होती है। अगर यह रक्त किसी भी कारण से दूषित होगा तो शरीर का संचालन बहुत अधिक समय तक संभव ही नहीं होगा। कुछ इसी प्रकार भारत भूमि को एक शरीर के रूप में, यहां बहती नदी को धमनियों की तरह और नदियों में बहते जल को रक्त के रूप में देख सकते हैं।

वर्तमान में धमनी रूपी नदियों में रक्त रूपी बहने वाला पानी प्रदूषित हो चुका है। यही कारण है कि भारत की नदियां बहुत अच्छे हालातों में नहीं हैं। इन परिस्थितियों में शरीर रूपी भारत अपनी चेतना को साधते हुए अपना धर्म निभा सकता है। हालांकि इस सन्दर्भ में भारत सरकार से लेकर बहुत से सामाजिक संगठन व कार्यकर्ता नदी सुधार के कार्यों में गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं।

वर्तमान में देश राममय है और भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मनाकर अमृत काल की यात्रा पर निकल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के समक्ष आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर वाटर विजन 2047 का लक्ष्य तय किया है। अब जब लम्बी अवधि के बाद 22 जनवरी को भव्य श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है तो प्रभु राम के नदियों से किये गए मधुर व सम्मानित व्यवहार को अपनी सीख में उतारना होगा। भारत की नदियों का जल जब शुद्ध होगा तो यह जीवन और उससे संबंधित गतिविधियां समृद्ध होंगी।



## नवसंवत्सर : सृष्टि का प्रस्थान बिन्दु

**ह**म हर साल एक जनवरी को जिस नये साल की धूमधाम के साथ शुरुआत करते हैं, दरअसल वह ईसाई नववर्ष है। इसमें वैज्ञानिकता का अभाव है। 31 दिसम्बर के बाद रात के अंधेरे में इसके प्रारम्भ होने का कोई कारण अभी तक सामने नहीं आया है। इस नववर्ष का प्रकृति से कोई भी तालमेल नहीं है, लेकिन सच यही है कि पहली जनवरी को जो नववर्ष मनाया जाता है, वह अब करीब-करीब पूरे विश्व में मान्य हो गया है, या यूँ कहें, सुस्थापित हो गया है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर (तिथि पत्रक) भी कहते हैं। इसे पोप ग्रेगोरी अष्टम ने 1582 में तैयार किया था। इसे ईसाई देशों ने भिन्न-भिन्न वर्षों में स्वीकार किया। बाद के वर्षों में इसकी स्वीकारोक्ति अन्य अनेक देशों में हुई। चूंकि अंग्रेजों का शासन एक समय पूरे विश्व पर रहा, इसलिए इसको लोकप्रिय करने में शासकीय प्रश्रय की बड़ी भूमिका है। इसे स्थापित करने में बाजार की भी अहम् भूमिका है। यह पश्चिमी सभ्यता को पुष्पित और पल्लवित करता है। इसमें ईसाई परम्पराओं का पोषण है। इसे सम्राटों का भी कैलेंडर कहा जाता है।

इस नववर्ष को हम भारतीयों ने भी पूरी तरह अंगीकार कर लिया है। इसको मनाने में वैसे ही खुशी मिलती है जैसी पड़ोसी के बच्चे

भारतीय नववर्ष को पूरे धूमधाम से मनाये जाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यह पूरी तरह वैज्ञानिक है, भारतीय कालगणना पर आधारित है। प्रकृति पर अवलम्बित है। इसकी शुरुआत रात के अंधेरे में नहीं, सूरज की पहली किरण के साथ अह्लादित मन से होती है।

का जन्मदिन मनाने में होती है। तो क्या हम अपने बच्चे का जन्मदिन नहीं मनाते? मनाते हैं, पूरे धूमधाम से। उसी तरह अब भारतीय नववर्ष को पूरे धूमधाम से मनाये जाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यह पूरी तरह वैज्ञानिक है, भारतीय कालगणना पर आधारित है और प्रकृति पर अवलम्बित है। इसकी शुरुआत रात के अंधेरे में नहीं होती है, सूरज की पहली किरण के साथ अह्लादित मन से होती है। हमारे नवसंवत्सर की कोई अंग्रेजी तिथि निश्चित नहीं है, क्योंकि यह नक्षत्रों पर आधारित होता है। इसका निर्धारण पञ्चांग की गणना के अनुसार होता है। यह नववर्ष मानव-समाज को प्रगति पथ पर आगे बढ़ने का संदेश देता है। इस पर भारतीय संस्कृति की छाप है। खुशनुमा मौसम इसका स्वागत करता है। इस कैलेंडर की शुरुआत हर साल होली के बाद होती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन इसका प्रारम्भ होता है। नवरात्र का पहला दिन होता है। नौ देवियों की पूजा-अर्चना से

सामाजिक माहौल धार्मिक और उल्लासपूर्ण होता है।

हमारे भारतीय नववर्ष का प्रारम्भ कई महान घटनाओं से अभिन्न रूप से जुड़ा है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन भगवान विष्णु प्रथम अवतार मत्स्यावतार के रूप में धरती का कल्याण करने के लिए अवतरित हुए थे। ब्रह्मा द्वारा रचित सृष्टि का प्रथम दिवस है (ब्रह्म पुराण)। भगवान राम और धर्मराज युधिष्ठिर का इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन राज्यारोहण हुआ था। इसी दिन आर्य समाज की स्थापना हुई थी। सिंधी समाज के आराध्य भगवान झूलेलाल का इसी दिन जन्म हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आद्य सरसंघचालक डॉ. बलिराम हेडगेवार का जन्म भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही हुआ था। इसी दिन भारत में भारतीय कालगणना का प्रारम्भ माना जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही मां दुर्गा के नौ रूपों की शक्ति और भक्ति के प्रतीक नवरात्र का पहला दिन भी होता है। भारतीय कालगणना

का सम्पूर्ण उपक्रम प्रकृति से तादात्म्य रखकर किया गया। आमावस्या का अंधकार नष्ट होने के 15 दिन पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र होने के आधार पर इस मास का नामकरण चैत्र किया गया। यानी हमारे नववर्ष का पहला माह। इसी क्रम में विखा नक्षत्र से वैशाख, ज्येष्ठा से ज्येष्ठ, पूर्वाषाढा से आषाढ, श्रवण से श्रावणा, पूर्वमघपट नक्षत्र से भाद्रपद, अश्विनी से आश्विन (क्वार), कृतिका से कार्तिक, मृग से मार्गशीर्ष (अगहन), पुष्य से पौष, मघा से माघ और पूर्ण फाल्गुनी नक्षत्र से फाल्गुन माह का नामकरण हुआ।

हमारा नववर्ष (चैत्र शुक्ल प्रतिपदा) भारतीय समाज को हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ने का ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पर्व है जैसे होली, दीपावली, दशहरा, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस आदि। लेकिन यह अभी उतना प्रचलन में नहीं है जितना अन्य त्यौहार हैं। मसलन नयी पीढ़ी के किसी व्यक्ति से अंग्रेजी वर्ष के 12 महीनों का नाम पूछो तो थड़ल्ले से जनवरी, फरवरी... दिसम्बर तक गिनवा देगा। लेकिन उससे हिन्दी महीनों के नाम पूछो तो शायद ही वह 12 महीनों के नाम एकबारगी बता सके। चैत्र, बैसाख, जेष्ठ, आषाढ... के आगे रुक सकता है, हालांकि भारतीय समाज अपने सारे शुभ कार्य वैज्ञानिक कालगणना पर आधारित पञ्चांग के अनुसार ही करता है। समाज के अवचेतन में यह गहराई तक सुस्थापित है।

### सृष्टि का प्रवाह

चैत्रे मासे जगद ब्रह्मा संसर्ज प्रथमे अहानि।  
शुक्ल पक्षे समग्रतु, तदा सूर्योदये सति।  
चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन सूर्योदय के समय ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। इसीलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारे नवसंवत्सर की शुरुआत मानी जाती है। यह हमारी सृष्टि का प्रस्थान बिन्दु है। पश्चिमी देशों में उनके अपने धर्मग्रंथों के आधार पर सृष्टि का कालखण्ड अधिकतम ढाई हजार वर्ष बताया जाता है, जबकि इस्लाम में इस विषय पर स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। कुल मिलाकर इस्लाम और ईसाई मजहब सृष्टि को बहुत

प्राचीन नहीं मानते हैं। इससे उलट भारतीय कैलेंडर और कालगणना विश्व में सबसे प्राचीन है। भारतीय कालगणना का आरम्भ सृष्टि के प्रथम दिन से माना जाता है। इस हिसाब से यह संवत् एक अरब 97 करोड़ 29 लाख 49 हजार वर्ष से भी अधिक पुराना है। वैदिक काल के साहित्य में ऋतुओं के आधार पर कालखण्ड के विभाजन द्वारा कैलेंडर के निर्माण का उल्लेख पाया जाता है। हिन्दू जीवन-दर्शन की मान्यता है कि ब्रह्माजी द्वारा प्रारम्भ की गयी मानवीय सृष्टि की कालगणना और भारत में प्रचलित संवत्सर न केवल हिन्दुओं, भारतीयों बल्कि सम्पूर्ण संसार का संवत्सर है। कहा जा सकता है कि यह अखिल ब्रह्माण्ड के आगमन का सूचक है। इसे सृष्टि संवत् भी कहते हैं।

**जैसे बारह माह होते हैं, उसी प्रकार साठ संवत्सर होते हैं। संवत्सर अर्थात् बारह महीने की कालविशेष की अवधि। सूर्य सिद्धांत के अनुसार संवत्सर बृहस्पति ग्रह के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। ज्योतिषीय आंकलन के अनुसार साठ संवत्सरों में बीस-बीस वर्ष के तीन प्रमुख काल खण्ड आते हैं।**

भारतीय कालगणना प्रकृति पर आधारित होने के कारण पूर्णतः वैज्ञानिक है। इसमें नक्षत्रों की चाल, स्थिति, दशा और दिशा से सम्पूर्ण वातावरण और मानवीय स्वभाव पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन के आधार पर कैलेंडर का निर्माण किया गया। हमारे यहां वैज्ञानिक गणना और सूर्य की महत्ता को ध्यान में रखते हुए रविवार को सप्ताह का पहला दिन माना गया। ऋषियों-मुनियों ने माना कि सातों ग्रह निरन्तर सूर्य की परिक्रमा करते हैं और एक निश्चित अवधि में हर ग्रह एक निश्चित स्थान पर जरूर आता है। ऋषियों ने इन्हीं ग्रहों के आधार पर सात दिनों के नाम रखे। इसमें दिन-रात शामिल हैं।

ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार दो प्रकार से

काल की गणना की जाती है- ईसा पूर्व व ईसा के बाद। इसमें जनवरी से प्रारम्भ होकर दिसम्बर तक कुल 12 महीने आते हैं। भारतीय परम्परा के अनुसार वार्षिक कालगणना शक संवत् व विक्रमी संवत् के आधार पर की जाती है। इसमें चैत्र मास से प्रारम्भ होकर वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रवण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन 12 माह आते हैं। प्रत्येक साल अथवा संवत् में कुल 27 नक्षत्र होते हैं, जो इस प्रकार हैं- अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ती, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद तथा रेवती। प्रत्येक माह में दो पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इस समय मौसम खुशनुमा रहता है। वनस्पतियों ने नवश्रृंगार किया हुआ होता है। नयी कोपलें फूट रही होती हैं। नवसंवत्सर के समय वातावरण बहुत सुरम्य रहता है, न ज्यादा ठंडक होती है न ज्यादा गर्मी।

अगर कालगणना को ज्योतिषीय आधार के अनुरूप विश्लेषित करें, तो हम पाएंगे कि चंद्रमास के अनुसार चैत्र मास के शुक्लपक्ष की प्रतिपदा वर्ष प्रतिपदा कहलाती है। इस दिन से ही नया वर्ष अर्थात् संवत्सर प्रारम्भ होता है। जैसे प्रत्येक माह के नाम होते हैं उसी तरह प्रत्येक वर्ष के नाम अलग-अलग होते हैं। जैसे बारह माह होते हैं, उसी प्रकार साठ संवत्सर होते हैं। संवत्सर अर्थात् बारह महीने की कालविशेष की अवधि। सूर्य सिद्धांत के अनुसार संवत्सर बृहस्पति ग्रह के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। ज्योतिषीय आंकलन के अनुसार साठ संवत्सरों में बीस-बीस वर्ष के तीन प्रमुख काल खण्ड आते हैं। इन्हें ब्रह्माविंशति (1 से 20), विष्णुविंशति (20 से 40) और शिवविंशति (40 से 60) कहते हैं।

(सुभाष चन्द्र सिंह, पूर्व राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश की पुस्तक 'भारतीय नववर्ष : पुनर्जागरण के आयाम' के अंश)

## नव ऊर्जा का पर्व नवरात्र



नीलम भागी  
लेखिका, जर्नलिस्ट, ब्लॉगर, टैवलर

**सृ**ष्टि के जड़, चेतन सभी पदार्थ निर्विवाद रूप से शक्ति के ही परिणाम हैं। यहां तक कि शरीर भी पंचतत्वों यानी क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा से बनी है। तभी, तो प्राण में जीवन शक्ति है। इसी शक्ति को जागृत करने का पर्व है नवरात्र। वैसे, तो ऋतु संधि का पर्व नवरात्र साल में चार बार पड़ता है। लेकिन इसमें दो गुप्त नवरात्र हैं और दो प्रकट रूप में चैत्र और शारदीय नवरात्र हैं। इन दोनों नवरात्र में 6 महीने का अन्तर होता है। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा हिन्दू नववर्ष से चैत्र नवरात्र शुरु होता है। यह 9 अप्रैल से 18 अप्रैल तक है। देश भर में अलग-अलग नाम से प्रचलित नवरात्र एक आध्यात्मिक उत्सव है। इस समय पेड़-पौधे भी नई-नई कोंपलों और फूलों से लदे होते हैं। इसलिए इसे वासंती नवरात्र भी कहा जाता है। वैज्ञानिक पहलू से नवरात्र के इन नौ दिनों में फलाहार, अल्पाहार, उपवास, नियम, अनुशासन से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। इससे आने वाले मौसम परिवर्तन के प्रभाव से भी रक्षा के लिए नव ऊर्जा मिलती है। साथ ही



**नवरात्र आध्यात्मिक और मानसिक ऊर्जा संचय का शक्ति पर्व है। जिसमें व्रत, संयम, यज्ञ, योग-साधना के जरिए इन रात्रियों में प्रकृति में निहित शक्ति से समन्वय स्थापित कर ज्ञान, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति में सकारात्मक विचार धारित कर कल्याणकारी मार्ग के पथिक बनते हैं।**

विविधताओं से भरे अपने देश के अधिकतर हिस्सों में नवरात्र में देवी के नौ स्वरूपों की पूजा होती है। इस दौरान देवी उपासना से आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। 9 दिन आत्म अनुशासन से मानसिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना भी सृजनात्मकता का प्रतीक है। इस तरह 9 विशेष दिनों का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व सृष्टि के कण-कण में दृष्टिगोचर होता है।

पश्चिमी भारत में इस दौरान गुड़ी पड़वा उत्सव महाराष्ट्रीयन और कोंकणी मनाते हैं। गुड़ी का अर्थ है

विजय पताका। महिषासुर, धूम्रलोचन, चंड मुंड, रक्तबीज असुरों का वध कर देवी ने असुरों पर विजय प्राप्त की। जिसके प्रतीक स्वरूप एक बांस पर बर्तन को उल्टा रखकर, उस पर नया कपड़ा लपेट कर पताका की तरह ऊंचाई पर रखा जाता है। जो दूर से देखने में ध्वज की तरह लगता है। मुख्यद्वार पर अल्पना और आम के पत्तों का तोरण तो सभी हिन्दू घरों में दिखता है। आम के पत्ते घट स्थापना में होते हैं। इसी तरह दक्षिण भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में उगादी का पर्व मनाते हैं। मंदिर जाते हैं और एक विशेष भोजन पचड़ी बनाया

जाता है। पचड़ी को नीम की कोंपले फूल, आम, हरी मिर्च, नमक, इमली और गुड़ से बनाते हैं। जो सभी स्वादों को जोड़ती है। तेलगु और कन्नड़ हिन्दू परंपराओं में पचड़ी प्रतीकात्मक है कि आने वाले वर्ष में हमें सभी अनुभवों की अपेक्षा करनी चाहिए और उनका लाभ उठाना चाहिए। पूर्वोत्तर भारत में चैत्र महीने की षष्ठी को "चैती छठ" मनाया जाता है। इसमें परिवार पवित्र नदियों में स्नान करके वहां वेदी बना कर पूजा का कलश स्थापित करता है और सूर्य को अर्घ्य देता है।

पूर्वोत्तर भारत में इस समय वसन्त के कारण प्राकृतिक सौन्दर्य की छटा निराली होती है। इसे रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू भी कहते हैं। बिहू की विशेषता है, इसे सब मनाते हैं कोई जाति, वर्ग, धनी, निर्धन का भेदभाव नहीं होता। यूनेस्को द्वारा 2016 में मानवता की सांस्कृतिक विरासत के रूप में दर्ज, पाहेला वैशाख बंगाल, त्रिपुरा, में उत्सव मंगल शोभा यात्रा का आयोजन होता है। झारखंड के आदिवासी, एक बड़े समुदाय के साथ सरहुल मनाते हैं और सरना देवी की पूजा करते हैं। उसके बाद से नया अन्न, फल, फूल खाते हैं और बीज बोया जाता है। यहीं से शादी विवाह की शुरुआत होती है। जूरशीतल भारत और नेपाल क्षेत्र में मैथिली समुदाय द्वारा मनाया जाता है। मैथिली, नववर्ष को जूरशीतल के उत्सव के रूप में मनाते हैं। मैथिल इस दिन भात और बारी (बेसन की सरसों के तेल में छनी) और गुड़ वाली पूरी बनाते हैं। इसी तरह पाना संक्राति, महा बिशुबा संक्राति, उड़िया नुआ बरसा, उड़िया नव वर्ष का सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव है। इस समारोह का मुख्य आकर्षण मेरु जात्रा, झामु जात्रा और चाडक पर्व है। कहीं कहीं पर छाऊ नृत्य, लोक



**हमारी संस्कृति के एक-एक पर्व का तत्त्वदर्शन वैज्ञानिक मानदंडों का निर्धारक है। भारत सभ्यताओं का नहीं, संस्कृति का राष्ट्र है। क्योंकि सभ्यताओं में संघर्ष हो सकता है, पर संस्कृति हमें जोड़ती है।**

शास्त्रीय नृत्य समारोह का आयोजन होता है। तमिल नववर्ष को पुथांडु उत्सव कहते हैं। तमिल महीने चितराई के पहले दिन पुथंडु, तमिलनाडु, पांडिचेरी, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, मॉरीशस में और विश्व में जहां भी तमिलवासी हैं, वहां मनाते हैं। इस दिन को तमिल नववर्ष या पुथुवरुशम के नाम से भी जाना जाता है। यह त्यौहार परिवार के सभी लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं। घरों में शाकाहारी भोजन वडा, पायसम, खासतौर पर 'मैंगो पचड़ी' बनाया जाता है। यह भी कहा

जाता है कि इस दिन देवी मीनाक्षी ने भगवान सुन्दरेश्वर से विवाह किया था।

केरल का नववर्ष मलयालम महीने मेदम को पहले दिन विशु मनाया जाता है। विशु केरल का महत्वपूर्ण उत्सव है। पिछली फसल के लिए भगवान का धन्यवाद किया जाता है और धान की बुआई की जाती है। परिवार के बुजुर्ग विशुकानी (विष्णु की झांकी) सजाते हैं। सुबह बच्चों की आंखों को ढक कर परिवार का बड़ा, बच्चे को विशुकानी के सामने लाकर आंखों से हाथ हटा लेता है। अर्थात् सुबह सबसे पहले भगवान के दर्शन करते हैं। बुजुर्ग बच्चों को विशुक्कनी (भेंट या रूपये) देते हैं। मंदिर जाते हैं। विशु भोजन करते हैं जिसमें 26 प्रकार का शाकाहारी भोजन होता है। यानि प्रकृति ने जो भी उस क्षेत्र में हमें दिया है उसका अधिक से अधिक विविधता के रूप में उपयोग विशु के भोजन में होता है। प्रतिपदा में सब अतीत को भूल कर आने वाले समय में खुशी और सकारात्मकता की कामना करते हैं।

अंत में नवमी को ब्रतियों द्वारा कन्या पूजन से व्रत का पारण करते हैं। क्योंकि ईश्वर के दूसरे रूप में मां (एक स्त्री) ही है। इसलिए हमने भी प्रकृति की शक्ति के नौ स्वरूपों को जगत जननी के भावों में ही अंगीकार किया। और दुर्गा के नौ स्वरूपों में प्रकृति के त्रिगुणात्मक शक्ति का दिग्दर्शन होता है। 51 शक्तिपीठों में शक्ति स्वरूपा जगदंबा के दर्शनों के लिए इस दौरान मौसम भी अनुकूल होता है। यानि हमारी संस्कृति के एक-एक पर्व का तत्त्वदर्शन वैज्ञानिक मानदंडों का निर्धारक है। भारत सभ्यताओं का नहीं, संस्कृति का राष्ट्र है, क्योंकि सभ्यताओं में संघर्ष हो सकता है, पर संस्कृति हमें जोड़ती है। ■

## आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम



स्व की प्रतिष्ठा से आत्मनिर्भरता में राष्ट्र हर दिन नयी उपलब्धि हासिल कर रहा है। इसी क्रम में गोरखपुर में सीबीजी प्लांट का उद्घाटन हुआ। यह ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर महत्वपूर्ण प्रयास

है। इस संयंत्र को इंडियन आयल ने लगभग 165 करोड़ रुपये की लागत से राज्य सरकार द्वारा आवंटित 18 एकड़ जमीन पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ स्थापित किया है। यह संयंत्र बायोगैस (सीबीजी) का उत्पादन करने के लिए लगभग 200 टन धान की पूवाल (पराली) एवं प्रेस मड तथा पशु गोबर का उपयोग कर प्रति दिन 20 टन कम्प्रेस्ड बायो गैस तथा 125 टन जैविक खाद का उत्पादन करेगा। इस संयंत्र से उत्पादित जैविक खाद से लगभग 9000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही सीबीजी संयंत्र से लगभग 20 TMT कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा, जो कि पर्यावरण सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा के लिए वरदान साबित होगा। गौरतलब है कि अब तक भारत में SATAT योजना के तहत 58 सीबीजी संयंत्र चालू किए गए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के स्वच्छ ऊर्जा परिदृश्य को 100 से अधिक बायोगैस संयंत्रों के साथ विस्तारित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत इसी वर्ष जनवरी माह में बंदायू में एचपीसीएल द्वारा स्थापित सीबीजी प्लांट से हुई थी।

## स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लोडिंग शुरू



भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और नेट जीरो के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के क्रम में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मिली है। कलपक्कम, तमिलनाडु में भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (500 मेगावाट) में कोर लोडिंग की शुरुआत हुई। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने परमाणु ईंधन चक्र के पूरे स्पेक्ट्रम में व्यापक क्षमताएं विकसित की हैं। यह ब्रीडर रिएक्टर खपत से अधिक ईंधन पैदा कर देश के प्रचुर थोरियम भंडार के पूर्ण उपयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा। भारत के सबसे उन्नत परमाणु रिएक्टर-प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के निर्माण और परिचालन के लिए, सरकार ने 2003 में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के निर्माण की मंजूरी दी थी। एक बार चालू होने के बाद, भारत रूस के बाद वाणिज्यिक रूप से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर परिचालित करने वाला दूसरा देश बन जाएगा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर शुरू में यूरेनियम-प्लूटोनियम मिश्रित ऑक्साइड ईंधन का उपयोग करेगा। ईंधन कोर के आसपास का यूरेनियम-238 ब्लैंकेट अधिक ईंधन का उत्पादन करने के लिए परमाणु रूपांतरण से गुजरेगा। इस चरण में ब्लैंकेट के रूप में थोरियम-232, जो अपने आप में एक विखंडनीय पदार्थ नहीं है, का उपयोग भी प्रस्तावित है। रूपांतरण द्वारा, थोरियम विखंडनीय यूरेनियम-233 बनाएगा, जिसका उपयोग तीसरे चरण में ईंधन के रूप में किया जाएगा। इस प्रकार एफबीआर; कार्यक्रम के तीसरे चरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अंततः भारत के प्रचुर थोरियम भंडार के पूर्ण उपयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा। जिससे बाद में बिजली का उत्पादन होगा।

## पूर्वी भारत की पहली हनी टेस्टिंग लैब

किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पारंपरिक खेती के अलावा व्यावसायिक खेती के लिए भी उन्हें सुविधा और ट्रेनिंग उपलब्ध करायी जा रही है। इसी क्रम में रांची में देश की पांचवीं एवं पूर्वी क्षेत्र की पहली अत्याधुनिक वृहद शहद परीक्षण प्रयोगशाला तथा



एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र का शिलान्यास हुआ। यह एक तरह से पूर्वी भारत में मीठी क्रांति का आगाज है। बता दें कि अभी एनडीडीबी आनंद (गुजरात), आईएआरआई पूसा दिल्ली, आईआईएचआर बेंगलुरु एवं आईबीडीसी हरियाणा में ऐसी प्रयोगशाला है। रांची में नई लैब बनने से पूर्वी भारत हनी हब के रूप में विकसित होगा। साथ ही शहद उत्पादकों को घरेलू बाजार में विस्तार व निर्यात के अवसर भी मिलेंगे। गौरतलब है कि इस क्षेत्र की लगभग 30 फ्रीसदी भूमि जंगल से ढकी हुई है, जिसमें प्रचुर मात्रा में फसलें, फल, सब्जियां और जंगली पेड़ हैं, जो शहद उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। देश में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के उन्नयन के साथ ही किसान भी पिछले एक दशक से केंद्र सरकार की प्राथमिकता में हैं।



1. द्वारका धाम को किसने बसाया था।

- (A) प्रभु श्री राम (B) श्री कृष्ण  
(C) बलराम (D) युद्धिष्ठिर

2. शारदा मठ की स्थापना किसने की थी?

- (A) आदि शंकराचार्य (B) रामानुजाचार्य  
(C) निंबकाचार्य (D) बल्लभाचार्य

3. वैराग्य-संदीपनी के रचनाकार हैं?

- (A) सूरदास (B) कबीर दास  
(C) तुलसीदास (D) जयशंकर प्रसाद

4. कविराजमार्ग का संबंध किससे है?

- (A) तमिल साहित्य (B) भोजपुरी साहित्य  
(C) अवधी साहित्य (D) कन्नड़ साहित्य

5. अगला नव संवत्सर होगा?

- (A) 2081 (B) 2082  
(C) 2083 (D) 2084

6. नवरात्र का दूसरा दिन समर्पित है।

- (A) मां चन्द्रघण्टा (B) मां कूष्माण्डा  
(C) मां ब्रह्मचारिणी (D) मां शैलपुत्री

7. अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पिता थे।

- (A) नहुष (B) ययाति  
(C) नाभाग (D) अज



8. शैव पुराण की संख्या कितनी है?

- (A) 6 (B) 7  
(C) 8 (D) 9

9. समुद्र का पर्यायवाची शब्द है।

- (A) सुधाकर (B) पुष्कर  
(C) जह्ववी (D) पारावार

10. मजुली नदी द्वीप की पहचान किस रूप में है?

- (A) सांस्कृतिक केंद्र (B) भव्य मंदिर  
(C) प्रसिद्ध मठ (D) ऊंची पहाड़ी

### उत्तर

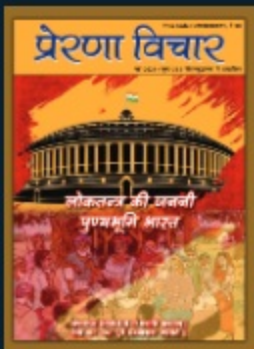
1. (B), 2.(A), 3.(C), 4.(D), 5.(A), 6.(C),  
7.(D), 8. (A) , 9. (D), 10. (A)

## हर दिन पावन

तिथि	विवरण
1 अप्रैल, 1889	डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार जयंती (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक)
2 अप्रैल, 1943	डॉ. बिन्देश्वरी पाठक जयंती (सुलभ समाजसेवी)
3 अप्रैल, 1997	त्रयम्बकराव जुमड़े पुण्यतिथि (संघ कार्यकर्ता)
4 अप्रैल, 1889	माखनलाल चतुर्वेदी जयंती (साहित्यकार एवं पत्रकार)
5 अप्रैल, 1986	हरमोहन लाल जी जयंती (संघ कार्यकर्ता)
6 अप्रैल, 1929	महाशय राजपाल पुण्यतिथि (सत्य पथ के बलिदानी)
8 अप्रैल, 1857	मंगल पाण्डे बलिदान दिवस, स्वतंत्रता सेनानी
9 अप्रैल, 1893	राहुल सांकृत्यायन जयंती (धुमक्कड़ साहित्यकार)
10 अप्रैल, 1875	आर्य समाज स्थापना दिवस
11 अप्रैल, 1827	ज्योतिबा फुले जयंती, समाज सुधारक
12 अप्रैल, 1921	सुन्दर सिंह भण्डारी जयंती, कुशल संगठक
13 अप्रैल, 1919	जलियांवाला बाग स्मृति दिवस
14 अप्रैल, 1891	डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती, संविधान निर्माता
15 अप्रैल, 1973	प्रभावती जी जयंती (स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सुधारक)
16 अप्रैल, 1966	नन्दलाल बोस पुण्यतिथि (प्रकृति के अनुपम चितेरे)
17 अप्रैल, 1966	जयंत सहस्रबुद्धे जयंती (भारतीय विज्ञान परम्परा के साधक)
18 अप्रैल, 1898	दामोदर हरि चापेकर बलिदान दिवस, स्वतंत्रता सेनानी
19 अप्रैल, 1864	महात्मा हंसराज जयंती, महान शिक्षाविद
20 अप्रैल, 1964	पी.टी. उषा जन्मदिवस, उड़नपरी
21 अप्रैल, 1858	गणपतराय बलिदान दिवस, क्रांतिकारी
22 अप्रैल, 1969	योगेश चन्द्र चटर्जी पुण्यतिथि, स्वतंत्रता सेनानी
24 अप्रैल, 2009	रामचंद्र वीर पुण्यतिथि, अनशनव्रती महात्मा
25 अप्रैल, 1925	यशवंत वासुदेव केलकर जयंती, कुशल कार्यकर्ता
26 अप्रैल, 1864	गुरुदत्त विद्यार्थी जयंती (डी.ए.वी. कॉलेज के सूत्रधार)
28 अप्रैल, 1858	जोध्यासिंह अटैया बलिदान दिवस, क्रांतिकारी
29 अप्रैल, 1923	गीता प्रेस स्थापना दिवस
30 अप्रैल, 1870	दादासाहब फाल्के जयंती (भारतीय फिल्मों के पितामह)



हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए स्कैन करें



प्रेरणा विचार पत्रिका की सदस्यता लेने के लिए स्कैन करें

पाठकगण प्रेरणा विचार पत्रिका के बारे में अपने सुझाव एवं प्रतिक्रिया, 'संपादक के नाम पत्र' शीर्षक से हमारी ई-मेल आईडी (prenavichar@gmail.com) या वाट्सएप नम्बर (9354133708) पर भेज सकते हैं। चुने हुए पत्रों को पत्रिका के अगले अंक में प्रकाशित किया जायेगा।



@PRERNAVICHAR



+919354133708



विभिन्न मंचों से प्रेरणा विचार पत्रिका का विमोचन